

3 | **राजधानी**
लाल बत्ती जंप करने वालों की खैर नहीं

6 | **अभिमत**
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का प्रयास

11 | **विदेश**
हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित

12 | **स्पोर्ट्स**
शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे सूर्य कुमार

RNI NO.DELHIN/2012/48369

वर्ष 12 अंक 134

नई दिल्ली, बुधवार, 20 मार्च, 2024

पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3

नगर संस्करण



नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com



आठ नए मंत्रियों के साथ हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार राष्ट्रीय-9

दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित

राजेश कुमार । नई दिल्ली

खराब होती वायु गुणवत्ता के कारण बढ़ती चिंताओं के बीच ख़िस संगठन आईक्यू एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि भारत 134 देशों में से तीसरा सबसे प्रदूषित देश है, जिसमें बांग्लादेश (79.9) और पाकिस्तान (73.7) के बाद औसत वार्षिक पीएम 2.5 सांद्रता के साथ 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली एक बार फिर सबसे खराब वायु गुणवत्ता के साथ दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले प्रदूषित राजधानी के रूप में सामने आई है। जबकि बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है। राष्ट्रीय राजधानी को 2018 से लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा मिला है, जबकि बेगूसराय को 2022 की रैंकिंग में जगह ही नहीं मिली थी।

2023 में भारत में हवा की गुणवत्ता पिछले वर्ष की तुलना में खराब हो गई है, जब औसत पीएम 2.5 स्तर 53.3 के साथ भारत सबसे प्रदूषित सूची में आठवें स्थान पर था। वार्षिक औसत पीएम 2.5 सांद्रता 2022 में 53.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की तुलना में 2023 में थोड़ा बढ़कर 54.4 पीएम 3 हो गई और भारत आठवें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान पर रहा। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया



देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है और परिणाम जल्द ही दिखाई देंगे। उन्होंने कहा, मैंने रिपोर्ट का विवरण नहीं देखा है और मुझे नहीं पता कि इसमें किस समयावधि को शामिल किया गया है। 2014 के बाद से, पीएम10 और पीएम2.5 के स्तर का विश्लेषण किया गया है और उनमें लगातार गिरावट

देखी गई है। 2022 में, औसत पीएम10 223 था और 2023 में यह घटकर 219 हो गया। पीएम2.5 का स्तर 2022 में 103 से बढ़कर 2023 में 106 हो गया। हम विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहे हैं और परिणाम दिखेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया के सभी चार सबसे प्रदूषित देश एशियाई क्षेत्र में हैं। इनमें बांग्लादेश, भारत, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान

शामिल हैं। इसके अलावा, यह क्षेत्र शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित वैश्विक शहरों का घर है। इसमें दिल्ली और लाहौर जैसे अत्यधिक आबादी वाले और ऐतिहासिक रूप से प्रदूषित शहर शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से नौ भारत में हैं, जिसमें पिछले साल के छह से अधिक शहर हैं। इस बीच, शीर्ष 50 में 42 शहर भारत के हैं जबकि पहले इस श्रेणी में 39 शहर थे। आश्चर्यजनक रूप

से शीर्ष 100 में 83 शहर भारतीय हैं (पिछले दो वर्षों में 63 और 65 से अधिक)। 2022 में दिल्ली का पीएम 2.5 स्तर 89.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बढ़कर 2023 में 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। इसके साथ यह पूरी सूची में 6वें स्थान पर रहा। दिलचस्प बात यह है कि 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत पीएम 2.5 सांद्रता के साथ बेगूसराय वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगर क्षेत्र के रूप में सामने आया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पूर्वी भारतीय राज्य बिहार का बेगूसराय है। इसका प्रदूषण स्तर औसतन 118.9 माइक्रोग्राम/घन मीटर रहा, जो सुरक्षित सीमा से 24 गुना अधिक है। सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है जो 79.9 माइक्रोग्राम के साथ सुरक्षित सीमा से 15 गुना अधिक है।

रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी भारत और दिल्ली में फसल जलाने, वाहन उत्सर्जन, कोयला जलाने, अपशिष्ट जलाने, गर्मी और खाना पकाने के लिए बायोमास जलाने से निकलने वाले धुएँ से जुड़ रहे हैं। उत्तरी भारत और पड़ोसी पाकिस्तान में वार्षिक फसल जलाने के परिणामस्वरूप नियमित रूप से दिल्ली में वायु गुणवत्ता आपातकालीन स्तर तक अनुभव किया जा सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने नवंबर में दिल्ली के धुंध को साफ करने में मदद के लिए संभावित समाधान (शेफ पेज 9)

सीए पर रोक लगाने संबंधी आवेदनों पर तीन हफ्ते में जवाब दे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

पीटीआई। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह करने वाले आवेदनों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को प्रभावी बनाने वाले नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला होने तक नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाए जाने का आग्रह किया था। वहीं, केंद्र ने अपनी ओर से कहा कि सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीनता। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पाद्रीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से केंद्र की ओर से पेश सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें 20 आवेदनों पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय चाहिए। न्यायालय ने इस पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए आवेदनों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

पीठ ने कहा, हम प्रथम दृष्टया कोई विचार व्यक्त नहीं कर रहे हैं...



हमें याचिकाकर्ताओं को सुनना है, हमें दूसरे पक्ष को सुनना है। मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल को होगी। आवेदनों में आग्रह किया गया है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का शीर्ष अदालत द्वारा निपटारा किए जाने तक संबंधित नियमों पर रोक लगाई जानी चाहिए।

संसद द्वारा विवादास्पद कानून पारित किए जाने के चार साल बाद केंद्र ने 11 मार्च को संबंधित नियमों को अधिसूचित करने के साथ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इस कानून में 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ईंदिरा जयसिंह ने कहा कि केंद्र को बयान देना चाहिए कि सुनवाई लंबित रहने तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। पीठ ने कहा, वे हमें यह कहने के हकदार हैं कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा समय दें। हम उन्हें आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय दे सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, समस्या यह है कि अगर नागरिकता की कोई प्रक्रिया शुरू होती है और किसी को नागरिकता मिल जाती है, तो कई कारणों से इसे उलटाना असंभव होगा और ये याचिकाएं निरर्थक हो जाएंगी। इसलिए, यह प्रक्रिया शुरू नहीं होनी चाहिए। जब एक वकील ने पूछा कि अगर बलूचिस्तान में प्रताड़ित कोई हिंदू व्यक्ति दिसंबर 2014 से पहले भारत आया है और उसे यहां नागरिकता दी जाती है, तो इससे किसी और के अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जयसिंह ने जवाब में कहा, क्योंकि उसे वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। पीठ के यह कहने पर कि मामले में अगली सुनवाई नौ अप्रैल को होगी, जयसिंह ने कहा, इस बीच, उन्हें बयान देने दीजिए कि वे किसी को नागरिकता नहीं देंगे।

भाजपा के किनारा करने के बाद पारस का केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मंगलवार को केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया और आरोप लगाया कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे की बातचीत में शामिल नहीं करके उनकी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ नाईसाफी कर रही है। पारस ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। इससे एक दिन पहले ही भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राज्य में अपने सीट-बंटवारा समझौते की घोषणा की थी और चिरगा पारसवान के नेतृत्व वाली लोजपा (रामविलास) को पांच सीट देने का ऐलान किया था। पारस ने संवाददाता सम्मेलन में अपने इस्तीफे के बारे में संक्षिप्त बयान दिया, लेकिन अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। प्रधानमंत्री मोदी के

मंत्रिमंडल में शामिल भाजपा के किसी सहयोगी दल के एक्मत्र नेता पारस ने सीट-बंटवारे को लेकर नाखुशी जताने से पहले प्रधानमंत्री को बड़ा नेता बताते हुए उन्मत्त आभार जताया। पारस ने कहा कि उन्होंने इमानदारी और निष्ठा के साथ राजग की सेवा की लेकिन उनके साथ नाईसाफी हुई। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी और खासतौर से मेरे साथ नाईसाफी हुई है। पारस की पार्टी के प्रवक्ता (शेफ पेज 9)



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दोहराई भारत की प्रतिबद्धता

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री ने मंगलवार को आतंकवाद और समुद्री डकैतों से लड़ने और हिंद महासागर क्षेत्र में परिवहन (नैविगेशन) की स्वतंत्रता की रक्षा करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री का यह बयान 40 घंटे के लंबे ऑपरेशन में अपने देश के जहाज और बलोरियाई नागरिकों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना के प्रति बलोरियाई राष्ट्रपति के आभार के जवाब में आया है। मोदी ने यह टिप्पणी बलोरिया के राष्ट्रपति रूमेन राडेव के एक संदेश के जवाब में की। राडेव ने अपने संदेश में सात बलोरियाई नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए आभार व्यक्त किया था। बलोरिया के राष्ट्रपति ने अपहृत बलोरियाई जहाज एमवी रूएन पर सफलतापूर्वक बचाव अभियान

चलाने के लिए भारतीय नौसेना के प्रति आभार व्यक्त किया।

मोदी ने बलोरिया के राष्ट्रपति एक्स हेंडल को संबोधित करते हुए सराहना की और सात बलोरियाई नागरिक के सुरक्षित होने पर संतोष जताया। ये बलोरियाई नागरिक जल्द घर लौट आएंगे। प्रधान मंत्री ने एक्स पर पोस्ट एक संदेश में कहा, राष्ट्रपति रूमेन राडेव, आपके संदेश की सराहना करते हैं। हमें खुशी है कि 7 बलोरियाई नागरिक सुरक्षित हैं और जल्द आया है। मोदी ने यह टिप्पणी बलोरिया के स्वतंत्रता की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले साल अरब सागर में आठ बलोरियाई, नौ म्यांमारी और एक अंगोलन नागरिक के साथ 'रूएन' जहाज को पिछले साल



दिसंबर में समुद्री डाकुओं ने पकड़ लिया था। एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट में, बलोरियाई राष्ट्रपति ने कहा, अपहृत बुल्गारियाई जहाज 'रूएन' और 7 बलोरियाई नागरिकों सहित उसके चालक

दल को बचाने के लिए नौसेना की बहादुरी थी। एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट में, मेरा हार्दिक आभार। इस बीच, बलोरिया की विदेश मंत्री मारिया गेब्रियल ने शनिवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि उन्होंने

एमवी रूएन पर भारतीय नौसेना के ऑपरेशन के लिए बलोरिया में भारतीय राजदूत संजय राणा से बातचीत की और बलोरियाई नागरिकों को बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

फेसबुक पर हालिया पोस्ट में बलोरिया की विदेश मंत्री मारिया गेब्रियल ने कहा, आज, 16 मार्च को भारतीय नौसेना की मदद से, 14 दिसंबर, 2023 को अपहृत जहाज 'रूएन' के चालक दल को रिहा कर दिया गया, जिसमें सात बलोरियाई नागरिक भी शामिल थे। उन्होंने कहा, भारतीय सेना के प्रयासों के लिए धन्यवाद, जहाज के पूरे चालक दल को मुक्त कर दिया गया। सभी नाविकों का स्वास्थ्य अच्छा है और बलोरिया में उनकी समय पर वापसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के संबंध में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि आठ

बलोरियाई, नौ म्यांमार और एक अंगोलन नागरिक के साथ जहाज 'रूएन' को पिछले साल दिसंबर में अरब सागर में समुद्री डाकुओं ने पकड़ लिया था। विदेश मंत्रालय, सभी संक्षम संस्थानों, क्षेत्र में बलोरिया गणराज्य के विदेशी प्रतिनिधित्व और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ निकट सहयोग में, बलोरियाई चालक दल को रिहा करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल है। सोफिया में 16 मार्च को विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत संजय राणा के साथ भी बातचीत हुई और भारतीय पक्ष से चालक दल की रक्षा के लिए हर संभव कार्रवाई करने का अतिरिक्त अनुरोध किया गया। उन्होंने अपने बयान में कहा, मैं बलोरियाई नाविकों को रिहा करने की प्रक्रिया में भारतीय पक्ष की सहायता के लिए बेहद आभारी हूँ।

ज्ञानवापी तहखाना मामले में 11 अप्रैल को कोर्ट करेगा सुनवाई

पीटीआई। वाराणसी

वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने के ऊपर की मुस्लिम श्रद्धालुओं को जाने से रोकने के अनुरोध वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख तय की है। अदालत ने हाल ही में तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी थी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि मुस्लिम पक्ष के सदस्यों ने मंगलवार को प्रभारी जिला न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत में कहा कि वे रमजान महीने के रोजे रख रहे हैं,

इसलिए उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसके बाद अदालत ने सुनवाई की तारीख 11 अप्रैल तय की है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि व्यास तहखाना के नाम से भी जाने जाने वाले तहखाने की छत काफी पुरानी और कमजोर है और इसके स्तंभों की मरम्मत की आवश्यकता है। नई याचिका दायर किए जाने से कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के 'व्यास तहखाना' में हिंदू प्रार्थनाएं जारी रहेंगी। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में जिला



अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी थी। यादव ने कहा था कि तहखाने के ऊपर मुस्लिम श्रद्धालुओं का घूमना या नमाज पढ़ना पुराने ढांचे के लिए अच्छा नहीं है, जिसकी मरम्मत की जानी चाहिए। जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया कि एक हिंदू पुजारी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर सकता है। अने पूजा-अर्चना काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित एक हिंदू पुजारी और याचिकाकर्ता द्वारा की जा रही है। पुजारी ने दावा किया है कि उनके दादा दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा करते थे।

मनमोहक फूलों की पंखुड़ियों से मनाएं होली का जश्न

अर्चना ज्योति । नई दिल्ली

होली खेलने वाले ध्यान दें। चूंक रंगों के दर्गों का त्योहार नजदीक है, इसलिए आपको होली की होली के आनंदमय उत्सव और उत्साह का अनुभव करने के लिए मयूरा के बांके बिहारी मंदिर या उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव की यात्रा करने की योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र द्वारका में इस्कॉन मंदिर में रंगों के त्योहार की जीवंत भावना में डूबने के लिए तैयार हो जाइए, जिसने मनमोहक फूलों की होली से लेकर उत्साही मटका फोड़ तक उत्सवों की एक आनंदमय श्रृंखला तैयार की है। लठ मार और मटका फोड़ होली, राधा और

कृष्ण के बीच शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। ये सभी परंपराएं 25 मार्च को एक छत के नीचे जीवंत हो रही हैं। इस प्रकार, इस शुभ अवसर से जुड़ी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की झलक मिलेगी। होली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल होली होलिका दहन के एक दिन बाद 25 मार्च को मनाई जा रही है। इस्कॉन द्वारका के उपाध्यक्ष श्री गौर प्रभु ने पायनियर को बताया कि होली का बहुप्रतीक्षित त्योहार 25 मार्च को श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में बहुत धूमधाम और गहरी भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, न केवल फूलों की होली, लठमार होली, मटका फोड़ होली की कतार बनाई गई है बल्कि यहां कई रंगारंग



कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में भगवान के दर्शन करने और एक साथ होली मनाने आएंगे। उन्होंने कहा, इस्कॉन द्वारका की होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है; यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। फूलों की होली रंगों की पारंपरिक फुहारों को सुगंधित फूलों के नाजुक नृत्य में बदल देगी, जो हवा को उनकी मीठी सुगंध से भर देगी। ऐसी तरह, राधा और कृष्ण के बीच शाश्वत बंधन का सम्मान करने के लिए भक्तों के एक साथ आने पर हंसी और खुशी के बीच लठ मार होली खेली जाएगी। और स्वादिष्ट व्यंजनों के बिना उत्सव कैसा? श्री गौर प्रभु ने आगे कहा कि पूरे दिन लाखों व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा, 250 किलोग्राम केक का

भोग भगवान को लगाया जाएगा और भक्तों के बीच वितरित किया जाएगा। इस्कॉन द्वारका में होली बहुत ही सात्विक और सुंदर तरीके से मनाई जाएगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण के आसपास हर्षोल्लास के साथ-साथ उत्सव भी मनाया जाएगा। श्री गौर प्रभु ने कहा, हम चाहते हैं कि सभी निवासी यहां मंदिर आएँ और एक-दूसरे निवासी अंजना कश्यप पहले से ही उत्साहित हैं और उन्होंने इस्कॉन मंदिर में मनाए जाने वाले उत्सव में शामिल होने की योजना बनाई है। (शेफ पेज 9)



कहा कि भाजपा में सफल राजनयिक पुष्टभूमि वाले संधू जैसे व्यक्ति की मौजूदगी पार्टी को मजबूत करेगी। भाजपा पंजाब में बहुसंख्यक सिखों के बीच अपना (शेफ पेज 9)



कांग्रेस का प्रत्याशियों पर मंथन जारी

● पार्टी नेताओं का मानना है कि मतदान में दो माह से भी अधिक समय, इतने लंबे समय तक चुनाव प्रचार करना मुश्किल

संजय राय | नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मैदान में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी ऐसा नहीं करेगी। रणनीति के तहत पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा और टाल सकती है। मंगलवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी राजधानी को लेकर कोई निर्णय नहीं किया गया। कांग्रेस पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। आप से गठबंधन में उसे तीन और आप को चार सीटें मिली हैं। आप अपने हिस्से की चारों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा सबसे पहले कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों के नाम भी तय नहीं किए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पहले

तीन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने में अभी और समय लग सकता है



प्रेस वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष अरविन्द लवली भाजपा उम्मीदवारों के सौ दिनों की कार्य योजना पर सवाल उठाते हुए।

उम्मीदवारों के नाम इसलिए तय और घोषित नहीं हुए क्योंकि प्रदेश इकाई की स्क्रॉनिंग कमेटी ने सीईसी को हर सीट पर तीन तीन नाम भेजा था। इस पर सीईसी ने स्क्रॉनिंग कमेटी को अपने स्तर पर ही एक एक नाम तय करके भेजने को कहा। राजधानी दिल्ली में मतदान छठें चरण में 25 मई को होना है। यानी अभी दो महीने से भी अधिक समय है। ऐसे में पार्टी अब दिल्ली को लेकर थोड़ी आश्वस्त हो गई है। वरिष्ठ पार्टी नेताओं का कहना है कि

इतने लंबे समय तक प्रचार कर पाना किसी भी उम्मीदवार के लिए संभव नहीं हो पाता। उसका खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है। इसलिए अभी कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने में समय लगा सकती है। यानी की उम्मीदवारों की घोषणा में अभी कम से कम दो सप्ताह लग सकता है। सूत्रों का कहना है कि अगर राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल के नेतृत्व वाली प्रदेश कांग्रेस की स्क्रॉनिंग कमेटी एवं प्रदेश नेतृत्व की चली तो सीईसी उत्तर पूर्वी दिल्ली से

पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, चांदनी चौकसे पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान के नाम पर मुहर लगा सकती है। और अगर आलाकमान के निर्देश पर सीईसी ने हस्तक्षेप किया तो तीनों जगह बदलाव हो सकता है। उस स्थिति में उत्तर पश्चिमी दिल्ली से पूर्व सांसद उदित राज, चांदनी चौक से पूर्व विधायक अलका लांबा और उत्तर पूर्वी दिल्ली से पैराशूट उम्मीदवार को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है।

भाजपा सांसदों के खिलाफ कांग्रेस लाएगी आरोपपत्र : लवली

नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविन्द सिंह लवली ने लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों के सौ दिनों की कार्य योजना पर सवाल उठाए हैं। लवली ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा के सांसदों ने क्या योगदान किया, यह बताने की बजाय चुनाव जीतने के बाद अगले 100 दिनों में वे क्या करेंगे उसकी चर्चा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सभी संसदीय क्षेत्रों की प्रतिज्ञा रैली में लोगों से लगातार कहा था कि भाजपा सांसदों ने 10 वर्षों में कुछ नहीं किया और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने उम्मीदवार बदल देगी, जो दिल्ली वासियों के सामने है। अरविन्द सिंह लवली ने कहा कि कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 में नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार दिया था। जिससे बाद में रद्द कर

समन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

● न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की पीठ बुधवार को करेगी सुनवाई

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। इस बीच केजरीवाल ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी किए गए 9 समन के खिलाफ चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मामले में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की पीठ की पीठ बुधवार को सुनवाई करेगी। प्रवर्तन निदेशाल द्वारा जारी नौवें समन में उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल ने इन समन को अवैध बताते हुए उनके जवाब में पेश होने से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 में नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार दिया था। जिससे बाद में रद्द कर



दिया था। इस दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद, सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार पर एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप धन शोधन की जांच हुई। जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि शराब नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। शराब नीति मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार जिक्र किया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आरोपी आबकारी नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनुचित रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हुआ, जिसके बदले में उन्होंने आम

आदमी पार्टी को रिश्तत दी। दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन मामले में पिछले आठ समन में से छह समन पर पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ दायर दो शिकायतों पर शनिवार को केजरीवाल को जमानत दे दी थी। उधर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन पर कोई स्थाना आदेश नहीं लगाया है और इससे यह स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल प्रथम दृष्टया दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी जमानत को राहत न समझे। अब अरविंद केजरीवाल भी जमानत पर चल रहे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लीग में शामिल हो गए हैं।

हजारों करोड़ों का शराब घोटाला अब 100 करोड़ पर आ गया है : भारद्वाज

● बोले, जो विपक्षी नेता सत्ता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं उनको पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी के नेता ने दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय बार बार समन भेजने के बावजूद जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर पाई तो अब सीबीआई से गिरफ्तार कराने की साजिश रची जा रही है। ईडी द्वारा शराब नीति घोटाले में केजरीवाल पर 100 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार करने के आरोप का प्रेस नोट जारी करने पर आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ों का तथाकथित शराब घोटाला अब 100 करोड़ पर आ गया है।

इस संबंध में भी ईडी आज तक एक पैसे के लेनदेन का कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है। सीधे भारतवाज ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय के 30 अप्रैल 2023 के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा, कि इस आदेश में न्यायाधीश ने साफ तौर पर इस



केजरीवाल पर शिकंजा कसता देख आप नेता बौखलाए: सचदेवा

नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल पर कानून का शिकंजा कसता देख आम आदमी पार्टी नेता इतना बौखला गये हैं कि वे यह भी भूल गये हैं कि जांच एजेंसी हर हाई प्रोफाइल केस की महत्वपूर्ण तारीख पर बयान जारी करती है। जांच एजेंसियां ईडी एवं सीबीआई लगातार शराब घोटाले के साथ ही जलबोर्ड आदि मामलों की जांच कर रही हैं और पहले भी मामले की कानूनी प्रगति पर बोलती रही हैं। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि जब शराब घोटाले की जांच में बड़ी प्रगति हुई तो जांच एजेंसी ने के कविता के बयान के आधार प्रेस वक्तव्य जारी कर स्पष्ट किया कि अब इस केस में बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है।



बात को कहा है, कि ईडी द्वारा 100 करोड़ रुपए के लेनदेन का आरोप केवल एक बरस का विषय है और इस संबंध में ईडी की ओर से कोई भी तथ्य या साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सोशल मीडिया कंटेंट पर नजर रखेंगे नोडल अधिकारी

● लोक सभा चुनाव के दौरान आपतिजनक संदेश पर नजर रखेगी दिल्ली पुलिस

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने लोकसभा चुनाव के दौरान एसएमएस या सोशल मीडिया मंचों के जरिए आपतिजनक संदेश फैलाने से रोकने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने और शिकायत के लिए एक नंबर व ईमेल एड्रेस जारी करने समेत कुछ कदम उठाए हैं।

पुलिस विभाग ने यहां जारी एक नोटिस में कहा कि संयुक्त पुलिस आयुक्त बी.एस. जायसवाल को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एसएमएस या विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के जरिए आपतिजनक संदेश फैलाने संबंधी मामलों से निपटने के लिए नोडल अधिकारी (सोशल मीडिया निगरानी एवं साइबर



क्राइम) नियुक्त किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पुलिस ने एक नंबर 8130099025 और एक ई-मेल भी जारी किया है, जहां लोग सोशल मीडिया पर आपतिजनक सामग्री से संबंधित मामलों की शिकायत कर सकते हैं। नोटिस में कहा गया है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे संदेशों में चुनाव कानूनों, आदर्श आचार संहिता और (निर्वाचन) आयोग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करके चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की क्षमता होती है। नोटिस में ऐसे आपतिजनक संदेशों का सामना करने वाले व्यक्तियों से तुरंत नोडल अधिकारी जायसवाल के समक्ष शिकायत देने का आग्रह किया गया है।

पुलिस ने शरजील की जमानत का किया विरोध

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी हिस्से में 2020 में हुए संप्रदायिक दंगे के सिलसिले में गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत गिरफ्तार छत्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की जमानत अर्जी का मंगलवार को उच्च न्यायालय में विरोध किया। पुलिस ने इमाम, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी और उमर खालिद सहित कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के संप्रदायिक दंगे का कथित मास्टरमाइंड होने पर आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में 53 लोग मारे गए थे।

इंडियन लीजेंड

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय दिल्ली में जी-एस.आई.एल. एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा आयोजित इंडियन लीजेंड अवार्ड्स 2024 का 9वां सफल और प्रतिष्ठित कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल इस अवसर पर सेलिब्रिटी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम में देश के 30 दिग्गजों को इंडियन लीजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। दीप प्रज्वलन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वामी चक्रपाणि महाराज (अध्यक्ष - रावजी अखिल हिंदू महासभा) और विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मेजर जनरल

अवार्ड से 30 लोग सम्मानित



सेवानिवृत्त प्रमोद कुमार सहगल, पद्मश्री जीतेंद्र सिंह शंटी, योगी प्रियव्रत अनिमेष, महंत के. एल शर्मा, डॉ. संदीप मारवाहा और प्रोफेसर एम.एन होडा, अलका शर्मा, नरेन्द्र वशिष्ठ (एस्ट्रोलॉजर) ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को गरिमा बढ़ा

दी। बॉलीवुड गायक अशोक मस्ती, प्रसिद्ध गायक एम.डी. देसी रॉकस्टार, अभिनेत्री शिवानी शर्मा, मशहूर हरियाणवी गायक विकास कुमार और अभिनेक खंडेलवाल, ममाशा म्यूजिक कंपनी के निदेशक एवं निर्माता नीरज जैन ने मनमोहक प्रस्तुतियां दीं।

यातायात पुलिस की सख्ती: लाल बत्ती जंप करने वालों की खैर नहीं

● प्रमुख सड़कों और जंक्शनों पर उडी रडार-आधारित रेड-लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम लगाए

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

यातायात नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस शहर में लालबत्ती की अनदेखी और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब तकनीक का सहारा लेगी।

पुलिस का कहना है कि वाहन चालकों के यातायात नियमों का उल्लंघन करने से पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों समेत खुद वाहन चालकों का जीवन को खतरे में डाला जाता है। साथ ही ट्रैफिक जाम की भी समस्या उत्पन्न होती है। इसके महनेजर यातायात पुलिस ने आरोपियों पर नकेल कसने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित



कराने के मकसद से एक मुहिम शुरू किया है। यातायात पुलिस का कहना है कि इस अभियान खास बात यह है कि लाल बत्ती जंप करने की घटनाओं की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और आरोपियों की पहचान करने के लिए प्रमुख चौराहों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर निगरानी तंत्र को मजबूत किया है।

त्वरित प्रतिक्रिया और यातायात नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक स्थानों पर अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया है। ये अधिकारी उल्लंघन करने वालों को तुरंत दंडित करने के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरणों से लैस रहेंगे। इस पहल को व्यापक जन जागरूकता

अभियानों द्वारा पूरक बनाया गया है जिसका उद्देश्य मोटर चालकों को लाल बत्ती जंप करने से जुड़े खतरों के बारे में शिक्षित करना है। सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से, ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार ड्राइविंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सूचनात्मक संदेश प्रसारित कर रही है।

तकनीकी का लाभ उठाते हुए यातायात पुलिस प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नवीन समाधान तैयार रही है। इसमें यातायात उल्लंघनों की सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग और प्रबंधन के लिए सीसीटीवी कैमरे, स्वचालित निगरानी प्रणाली और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग शामिल है यातायात पुलिस ने पूरे शहर की प्रमुख सड़कों और जंक्शनों पर उडी रडार-आधारित रेड-लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम (आरएलवीडी) स्थापित किया है। यह रेड-लाइट डिटेक्शन सिस्टम का उपयोग करके नागरिकों के लिए सड़क सुरक्षा का पुरस्कार बढ़ावा देने और अनुशासन सुनिश्चित करना है।

यह रास्ते में लाल बत्ती पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का पता लगाता है और बिना किसी मानवीय संपर्क के मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत ई-चालान के लिए नियंत्रण कक्ष को विवरण भेजता है।

इन प्रणालियों का उद्देश्य उल्लंघनकर्ताओं पर चौबीसों घंटे निगरानी कर केस चलाना है, क्योंकि हर जगह और चौबीस घंटे पुलिस कर्मियों का तैनात रहना मुश्किल है। यातायात पुलिस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में, आरएलवीडी कैमरों का उपयोग करने वाले प्रवर्तन प्रयासों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में चालान काटा गया। जिसमें निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर 59,937 नोटिस जारी किए गए। हालाँकि, अगले वर्ष, 2023 में, आरएलवीडी अभियोजनों में काफी कमी देखी गई। केवल 21,089 नोटिस जारी किए गए। निर्धारित समय सीमा के भीतर 69,296 नोटिस जारी किए जाने के साथ एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।

मोबाइल टावर के उपकरण चोरी करने वाले 15 पकड़े

● आरोपियों से 15 पावर बैटरी, रेडियो यूनिट आदि बरामद

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

अपराध शाखा मोबाइल टावरों से आरआरयू, बीबीयू और संबंधित सहायक उपकरण चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए। 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मोबाइल टावर उपकरणों की चोरी बिक्री खरीद में शामिल रहे हैं। इन लोगों के कब्जे से मोबाइल टावर के उपकरणों में 15 पावर बैटरी, 20 बंडल केबल, 2 आरएएसपी, रेडियो यूनिट आदि



बरामद किए गए हैं। जब्त सामान की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये है। आरोपियों की गिरफ्तारी से दिल्ली एनसीआर में मोबाइल टावर उपकरणों से सामान की चोरी के 63 मामलों का खुलासा हुआ है। अधिकारी ने अपनी शिकायत में बताया उपकरण चोरी किये जा रहे हैं। उपकरण चोरी होने के कारण ग्राहकों को कॉल करने और इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल में परेशानी होती है।

लिंग संवेदीकरण विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन

फरीदाबाद। प्राचार्या डॉ. रुचिरा खुल्लर के कुशल मार्गदर्शन एवं महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉ. चारु मिड्डा के कुशल मार्गदर्शन में महाविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लिंग संवेदीकरण विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डॉ. नीनू सैनी, डॉ. उमा शेखावत और डॉ. ललितला चौधरी ने छात्रों को इन संवेदनशील विषयों को संबोधित करने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। बीस से अधिक छात्रों ने अपने दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में सक्रिय रूप से भाग लिया। शीर्ष तीन स्थान प्राची (प्रथम), विकेश (द्वितीय), और आकाश (तीसरे) ने हासिल किये। विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए।

हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है बादशाहपुर, दूसरे नंबर पर गुरुग्राम

फरीदाबाद जिला की बडख़ल है तीसरी बड़ी सीट

गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में 24.94 लाख से अधिक हैं मतदाता

गुरुग्राम लोकसभा में हैं 989 शहरी व 1418 ग्रामीण पोलिंग बूथ

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

फरीदाबाद, रेवाड़ी व गुरुग्राम को मिलाकर तीन जिलों के लोकसभा क्षेत्र में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ी विधानसभा है। यह गुडगांव लोकसभा ही नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी विधानसभा है। यहां चार लाख 62 हजार 765 मतदाता हैं। दूसरे नंबर पर गुरुग्राम विधानसभा है, जिसमें चार लाख 5 हजार 814 मतदाता हैं।

तीसरे नम्बर पर फरीदाबाद जिला की बडख़ल विधानसभा है। 2019 के चुनाव में यहां 2 लाख 75 हजार 347 मतदाता थे। यह आंकड़ा अब बढ़ चुका है। गुरुग्राम लोकसभा की बात करें



गुरुग्राम लोकसभा का मैप।

तो यहां 24.94 लाख से अधिक मतदाता हैं। अगर 2024 के घोषित लोकसभा चुनाव से पहले कुछ नए वोट बने तो इस संख्या में इजाफा हो सकता है। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में गुरुग्राम, रेवाड़ी और मेवात जिला की नौ विधानसभा सीटें बावल, रेवाड़ी, पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम, सोहना, नूंह, फिरोजपुर झिरका व पुन्हना हैं।

गुडगांव लोकसभा से रेवाड़ी जिला से बावल विधानसभा क्षेत्र में दो लाख 24 हजार 458 मतदाता व रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में दो लाख 46 हजार 801 मतदाता हैं। गुरुग्राम जिला की पटौदी विधानसभा क्षेत्र में दो लाख 45 हजार 787 मतदाता, बादशाहपुर में चार लाख 62 हजार 765 मतदाता, गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में चार लाख 5 हजार 814 व सोहना विधानसभा क्षेत्र में दो लाख

श्री शीतला माता के चैत्र मेले में श्रद्धालुओं को मतदान के प्रति किया जाएगा जागरुक

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

लोकसभा चुनावों में अधिक से अधिक लोग मतदान करें, इसके लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। देश में लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इसी बीच यहां श्री शीतला माता मंदिर में आगामी 26 मार्च से 23 अप्रैल तक चैत्र मेला आयोजित किया जा रहा है।

यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को इस लोकतंत्र के पर्व को लेकर जागरुक किया जाएगा। जागरुकता के लिए मेले में मतदाता जागरुकता के बोर्ड भी लगाए

गुरुग्राम के श्री शीतला माता मंदिर में 26 मार्च से 23 अप्रैल तक होगा चैत्र मेला

जाएँ। श्री शीतला माता मंदिर में चैत्र मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले के आयोजन को लेकर श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीसी निशांत कुमार यादव ने चैत्र मेले के आयोजन को लेकर मंगलवार को मंदिर परिसर में संबंधित



श्री शीतला माता मंदिर में चैत्र मेले को लेकर बैठक लेते डीसी निशांत कुमार यादव।

अधिकारियों तथा बोर्ड के सदस्यों की बैठक ली।

इस दौरान श्री माता शीतला देवी मंदिर श्राइन बोर्ड के सीईओ एवं सोहना के एसडीएम सोनू भट्ट भी मौजूद रहे। बैठक में डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि

उत्तर भारत का एक प्रमुख आस्था स्थल होने के चलते श्री शीतला माता मंदिर में आयोजित होने वाले चैत्र मेले में करीब आठ लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। मेले में आने वाले श्रद्धालु गुरुग्राम शहर की एक बेहतर

23 को शहीदी दिवस मनाएंगे कर्मचारी



फरीदाबाद। हड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन रजिस्टर नंबर-1266 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ की बैठक सर्कल प्रधान ओमप्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक का संचालन ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के सचिव रविंद्र ने किया। मीटिंग को सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान अजीत और पूर्व सर्कल सचिव धर्मवीर वैष्णव ने भी संबोधित किया।

सेक्टर-12 के ओपन एयर थिएटर में संपन्न हुई इस बैठक में 23 मार्च को शहीद ए आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहीदी दिवस जोर-जोर से बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में कर्मचारियों का वेतन का भुगतान समय पर करने, ईएसआई और पीएफ की राशियों को जमा करने, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधीन कार्यरत सफाई के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की मांग की गई। बैठक को महेंद्र, अनिल, संजीव, जिले सिंह, कन्हैया, योगेश बेनीवाल, बिजेंद्र और राजपाल ने भी संबोधित किया।

नगर परिषद ने अरावली अंसल में चिन्हित किए 45 फार्म हाउस, जल्द चलेगा पीला पंजा

पायनियर समाचार सेवा। सोहना

नगर परिषद ने वाई एक के गांव रायसीना से लगती अरावली पहाड़ी क्षेत्र में ट्रस्ट की 46 एकड़ जमीन समेत 45 फार्म हाउसों का अवैध निर्माण होने पर चिन्हित किया है। उक्त अवैध निर्माण को गिराने के लिए परिषद प्रशासन ने जिला उपायुक्त पत्र लिखकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मांग की है। ताकि चिन्हित किए गए अवैध निर्माण को धराशाही किया जा सके।

नगर परिषद ने अरावली की अंसल पहाड़ी में धड़ल्ले से चल रहा फार्म हाउस व ट्रस्ट की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कमर कस रहा है। परिषद प्रशासन ने हाल ही में अरावली अंसल क्षेत्र में सर्वे करते हुए करीब 45 फार्म हाउस में अवैध निर्माण से लेकर ट्रस्ट की जमीन पर कॉलोनी काटने के इरादे से कंकरी की पक्की सड़क बनाने के दौरान अवैध रूप से खनन व पेड़ों की कटाई को जा रही है।

नगर परिषद प्रशासन ने अरावली



सोहना नगर परिषद के वाई-एक के गांव रायसीना से लगती अरावली अंसल पहाड़ी में चलते अवैध निर्माण कार्य।

अंसल में अवैध कार्यों के खिलाफ एक बार फिर से अभियान चलाने की योजना बनाई है।

अभियान की मंजूरी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाने की मांग की है। जैसे ही उपायुक्त द्वारा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट उपलब्ध करा दिया जाएगा। वैसे की परिषद प्रशासन अपना अभियान चलाते हुए धराशाही से तोड़ दिया जाएगा।

ट्रस्ट की जमीन पर अवैध कॉलोनी : जानकारों के अनुसार अरावली अंसल में स्थित बाबा ट्रस्ट की करीब 80 एकड़ जमीन में से 46 एकड़ पर अवैध कॉलोनी काटते हुए 120 के

लगभग फार्म हाउस बनाकर बेचे जा रहे हैं। कॉलोनी में रहने वालों को सुविधा देने के नाम पर पक्की सड़कों को एनजीटी के नियमों की ध्ज्नियां उड़ाई जा रही है।

जबकि उक्त जमीन पर शुरुआत में अस्पताल या कॉलेज खोले जाने के इरादे से ट्रस्ट संचाक का इरादा था। लेकिन उक्त समाज सेवी की मृत्यु हो जाने के बाद डीलरो द्वारा फार्म हाउस बनाकर बेची जा रही है।

वन विभाग और खनन विभाग की अदेखी : अरावली अंसल में चल रहा अवैध निर्माण के प्रति वन विभाग और खनन विभाग अधिकारी पूरी तरफ से अपनी आंखें बंद करके बैठे



चुनाव जीत कर विधानसभा में पहुंचेंगे। श्रे मेवात से बनी पहचान : 1996 में बंसीलाल सरकार में संजय सिंह के पिता कुवर सूरजपाल सिंह रेवणु मंत्री रहे थे। श्रे मेवात के नाम से पहचाने जाने वाले मेवात के दिग्गज नेता कंवर सूरजपाल सिंह के पुत्र संजय सिंह का जन्म नूंह मेवात के गांव उज्जनी में 4 नवंबर 1975 को हुआ था। 1997 में सरकार की परीक्षा सोहना में स्थित निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह मैमोरिल कॉलेज से उत्तीर्ण की थी।

छवि अपने मन मे लेकर जाए इसके लिए आयोजन से जुड़ी सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाए। उन्होंने बोर्ड के सदस्य व मेला प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि चैत्र मेले में सप्ताह के 3 दिनों रविवार, सोमवार और मंगलवार के दौरान श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ रहती है, उन दिनों में विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी सुनिश्चित करें। गुरुग्राम पुलिस, गृह रक्षी बल तथा मंदिर की प्राइवेट सिक्वेरिटी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभालेंगे। पुलिस को ट्रैफिक प्लान तैयार

करने के निर्देश : डीसी ने बैठक में उपस्थित पुलिस विभाग के अधिकारियों को मेला के दिनों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार करने के लिए भी कहा है, ताकि उन दिनों में मंदिर तक श्रद्धालुओं को पहुंचने में दिक्कत ना आए।

श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग की पूरी व्यवस्था हो और शहरवासियों को भी मंदिर के आसपास ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान प्रसाद विक्रेताओं की दुकानों व मुंडन वाले स्थानों पर निर्धारित रेट लिस्ट के बोर्ड लगाए जाएंगे।

श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल ने विधायक सुधीर सिंगला को दिया स्मृति चिन्ह



विधायक सुधीर सिंगला को स्मृति चिन्ह देते श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल के पदाधिकारी

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

धूमधाम से मनाए गए श्री श्याम वसंत महोत्सव की विधायक ने दी बधाई

श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का 36वां श्री श्याम वसंत महोत्सव का स्मृति चिन्ह सौंपने के लिए श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल गुरुग्राम की टीम विधायक सुधीर सिंगला के आवास पर पहुंची। मंगलवार को मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों ने विधायक को स्मृति चिन्ह सौंपा।

श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल पदाधिकारियों में संरक्षक सुनील सिंगला, प्रधान राजकुमार कौशिक, कोषाध्यक्ष सचिन मित्तल, पूर्व प्रधान विष्णु मंगला, मदन गोपाल सिंगला, डा. गजराज, अमित गोयल, विवेक सिंगला ने विधायक सुधीर सिंगला को स्मृति चिन्ह सौंपा। विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि श्री खाटू

श्याम प्रचार मंडल धर्म के प्रचार के लिए वर्षों से कार्यरत है। हर साल श्याम बाबा जी भव्य वसंत महोत्सव आयोजित करके गुरुग्राम में धर्म को बढ़ावा मंडल की ओर से किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अपने तीज-त्योहार मनाने और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए श्री खाटू श्याम प्रचार लगातार कार्यरत रहता है। सनातन धर्म के प्रति जागृति लाने का काम संस्था की ओर से किया जाता है। विधायक ने कहा कि समाज

में हर तरह से सेवा कार्यों को प्रचार मंडल बढ़ावा देता है।

विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि बाबा श्याम के फाल्गुनी मेला चल रहा है। मेले में श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए गुरुग्राम समेत देशभर से लाखों श्रद्धालु रोजाना दर्शन करते हैं। सभी श्रद्धालु मेला प्रबंधन द्वारा बताए जा रहे नियमों का पालन करें।

अपने शहर का गौरव बढ़ाएं। उन्होंने सभी को श्याम बाबा के फाल्गुनी मेले की बधाई देते हुए कहा कि बाबा के नाम से होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रमों में हमारी बड़ी संख्या में हाजिरी हो। उन्होंने मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों को श्री श्याम वसंत महोत्सव को भव्य तरीके से मनाना की शुभकामनाएं दीं।

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गुरुग्राम में चलाया जाएगा विशेष अभियान

गुरुग्राम। लोकसभा आम चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन गुरुग्राम द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव के मार्गदर्शन में जिला के सार्वजनिक स्थानों तथा शिक्षण संस्थानों में विशेष जागरुकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं एडीसी हितेश कुमार मीणा के मुताबिक लोकतंत्र में मताधिकार का विशेष महत्व होता है। जिला में बड़ी संख्या में युवा मतदाता इस बार अपने मताधिकार का पहली बार प्रयोग करेंगे। ऐसे में नव मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला के सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व अन्य शिक्षण संस्थानों को इस कार्यक्रम में भागीदार बनाया जाएगा। एडीसी ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नागरिक अस्पताल, सीएचसी व पीएचसी की स्लिप, गैस



एडीसी एवं स्वीप नोडल अधिकारी हितेश कुमार मीणा।

एजीसी की स्लिप व अन्य बिलों पर भी चुनाव का पर्व, देश का गर्व स्लोगन की स्टैंप लगाई जाएंगी ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं तक मतदान करने का संदेश पहुंचाया जा सके। इस कार्य में हरियाणा राज्य परिवहन विभाग व गुरुग्राम बसों के यात्रियों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही विकास सदन में मतदाता जिला के सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व अन्य शिक्षण संस्थानों को इस कार्यक्रम में भागीदार बनाया जाएगा। एडीसी ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नागरिक अस्पताल, सीएचसी व पीएचसी की स्लिप, गैस

Sensodyne वर्ल्ड ओरल हैल्थ डे के अवसर पर दिल्ली में निशुल्क डेंटल कैंप लगा रहा है

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

Haleon (पूर्व में GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) की ओर से अग्रणी ओरल केयर ब्रांड, Sensodyne भारत में 12 मार्च से 31 मार्च, 2024 के बीच निशुल्क डेंटल शिविर लगा रहा है। ये कैंप हर साल 20 मार्च को मनाए जाने वाले वर्ल्ड ओरल हैल्थ डे के अवसर पर Sensodyne के #BeSensitiveToOralHealth अभियान के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों द्वारा Sensodyne का उद्देश्य भारतीयों को ओरल केयर का महत्व समझाना और उन्हें फ्री डेंटल केयर निशुल्क प्रदान करना है।

हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 60 प्रतिशत लोगों को ओरल हैल्थ की समस्या है। जबकि डेंटल केयर प्राप्त करने की कोशिश केवल 5 प्रतिशत लोग ही करते हैं, और दौंतों के लिए



कोई बीमा भी नहीं होती है। Sensodyne इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न शहरों और गाँवों में 500 से ज्यादा निशुल्क डेंटल कैंप लगा रहा है। दिल्ली में लगाए जा रहे डेंटल कैंप में ओरल हैल्थ की विभिन्न समस्याओं, जैसे सेंसिटिविटी, मसूढ़ों की समस्याओं, कैंविटी, और दौंतों की ऊपरी पत के घिसने का समाधान प्रदान किया जाएगा। इन कैंपों में लोगों को ओरल केयर की दिनचर्या में सरल उपाय शामिल करने की शिक्षा दी जाएगी ताकि वो अपनी ओरल हाईजीन बनाकर रख सकें। जागरुकता बढ़ाने के लिए Sensodyne ने भारत में डेंटल क्लिनिक्स के आसपास लगभग 5000 फार्मसी के साथ साझेदारी की है, और वहाँ क्यूआर कोड लगाए हैं, जिनकी मदद से

ग्राहक नजदीकी निशुल्क डेंटल कैंस का पता लगा सकते हैं। विभिन्न शहरों में चलाए जा रहे इस अभियान के बारे में Ms Bhawna Sikka, Category Head-Oral Healthcare, Haleon India ने कहा, "Sensodyne का ये विश्वास है कि शरीर की पूरी सेहत में ओरल हैल्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण हम ओरल हैल्थ के बारे में शिक्षा बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता है, कि डेंटल चेकअप का लाभ हर व्यक्ति को मिल सके। इसको बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ Sensodyne 80 शहरों में अपने #BeSensitiveToOralHealth अभियान के अंतर्गत डेंटल कैंप लगा रहा है। इन कैंस एवं अन्य अभियानों द्वारा हम भारतीयों को अपनी ओरल हाइजीन बनाए रखने और उसे प्राथमिकता देने में समर्थ बनाना चाहते हैं।

सोहना विधायक संजय सिंह बने प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री

सोहना। सोहना से पहली बार विधायक बनें संजय सिंह को प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रीमंडल में राज्यमंत्री बनाया। नवनियुक्त प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री संजय सिंह को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। संजय सिंह को प्रदेश सरकार के मंत्रीमंडल में मंत्री बनाए जाने पर शहर में चारों तरफ जमकर आतिशबाजी चलाकर खुशियां मनाई जा रही है। प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनें सोहना विधायक संजय सिंह का राजनीतिक कैरियर संघर्षमय रहा है। जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत 1997 में गाँव उज्जनी जिला नूंह के सरपंच पद का चुनाव जीत कर की थी। संजय सिंह ने तीन बार विधानसभा का चुनाव हार कर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। वर्ष 2019 में सम्पन्न विधानसभा चुनाव में सोहना से चौथी बार राजनीतिक पारी खेली और भाजपा की टिकट पर



चुनाव जीत कर विधानसभा में पहुंचेंगे। श्रे मेवात से बनी पहचान : 1996 में बंसीलाल सरकार में संजय सिंह के पिता कुवर सूरजपाल सिंह रेवणु मंत्री रहे थे। श्रे मेवात के नाम से पहचाने जाने वाले मेवात के दिग्गज नेता कंवर सूरजपाल सिंह के पुत्र संजय सिंह का जन्म नूंह मेवात के गांव उज्जनी में 4 नवंबर 1975 को हुआ था। 1997 में सरकार की परीक्षा सोहना में स्थित निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह मैमोरिल कॉलेज से उत्तीर्ण की थी।

आदर्श चुनाव आचार संहिता की मर्यादाओं का पालन करेंगे प्रत्याशी : निशांत कुमार यादव

डिफेंसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सख्ती से की जाएगी

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में सभी राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार कहीं भी सरकारी भवन तथा निजी इमारतों, पर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगाएंगे। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत ऐसे मामले में प्रत्याशी या पार्टी के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। वे यहां लघु सचिवालय सभागार में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श



चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जिसका सभी पार्टियों व उम्मीदवारों को कड़ाई से पालन करना है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार किसी दूसरे प्रत्याशी पर कोई भी व्यक्तिगत, जातिगत, धार्मिक या पारिवारिक भवनाओं को ठेस पहुंचानी वाली बातें ना बोलें। आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई भी नया विकास कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। ना तो कोई उद्घाटन होगा ना ही किसी काम का शिलान्यास किया जाएगा। इसी प्रकार सरकार में शामिल जनप्रतिनिधि अब कोड ऑफ कंडक्ट के कारण

अधिकारियों की बैठक नहीं बुला सकता। ना ही कोई नए तबादले होंगे और ना ही नई नियुक्तियां की जाएंगी। इस प्रकार सरकारी विश्राम गृह का प्रयोग राजनैतिक बैठकों के लिए नहीं किया जाएगा।

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग ने अब सी-बिजिल के नाम से नया मोबाइल एप शुरू किया है। इस ऐप पर कोई भी नागरिक या उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता की अवहेलना कहीं हो रही है तो उसकी फोटो खिंच कर भेज सकता है। जिस पर सी मिनट में अवश्य कार्रवाई की जाएगी।

गुरुग्राम के लघु सचिवालय में लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक लेते डीसी निशांत कुमार यादव।

व्लादीमिर पुतिन

सत्ता पर पकड़ मजबूत

रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ऊर्जा से भरे हैं और सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत बनी हुई है। हालाँकि, आरोप हैं कि सत्ता के पीछे उनके प्रशासन ने अनेक हथकंडे अपना कर चुनाव से वैधता प्राप्त की है। पुतिन ने अपना नियंत्रण मजबूत किया है और 'तानाशाह' होने तथा चुनावी हेरफेर के आरोपों के बावजूद उनका लोकप्रिय समर्थन बना हुआ है। हालाँकि, रविवार को समाप्त तीन दिवसीय हालिया मतदान में अनेक रूसी नागरिकों ने कुछ मतदान केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन भी किए। चुनाव कानूनों और संस्थानों में परिवर्तन पुतिन के मनपसंद उपकरण हैं। रूसी नेतृत्व ने काफी समय से ऐसी नीतियां बनाई हैं जो मूलतः आलोचकों को खामोश करती हैं तथा असली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में बाधा डालती हैं। पुतिन और उनके सहायकों को चुनावी नियंत्रण चयनित ढंग से लागू करने, मीडिया की चयनित कवरेज तथा कठोर पंजीकरण नियमों से लाभ होता है। ऐसे में क्रैमलिन को लक्षित परिणामों की गारंटी करते हुए प्रतियोगी चुनाव प्रक्रिया प्रदर्शित करने का मौका मिल जाता है। इसके लिए विमर्श को अपने अनुकूल बनाया जाता है तथा विपक्षी स्वयं का प्रचार रोका जाता है। इसके साथ ही पुतिन ने अपनी ऐसे शक्तिशाली और दृढ़ नेता की छवि बनाई है जो बाहरी खतरों के मुकाबले रूस के हितों की रक्षा कर सकता है। पुतिन ने राज्य-संचालित मीडिया को अपने इशारे पर चलाने तथा स्वयं को देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए जरूरी 'व्यक्तित्व' के रूप में पेश करने में सफलता पाई है। पुतिन ने बाहरी युद्धों और भू-राजनीति का प्रयोग देश में लाभ उठाने के लिए किया है। उदाहरण के लिए, रूस की जनता ने व्यापक रूप से 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे का समर्थन किया था तथा इसे देश के भूभाग और गरिमा की वापसी की तरह देखा था।



भारी संख्या में रूसी नागरिक पुतिन को संभावित बाहरी आक्रमण के खिलाफ मजबूत ढाल की तरह देखते हैं जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है। पुतिन स्वयं को रूसी हितों का वैश्विक चैंपियन बता कर मतदाताओं का समर्थन और एकजुटता प्राप्त कर सकते हैं। इससे जनता की नजयें में उनके अधिकार को वैधता और स्वीकार्यता मिलती है। इसके साथ ही पुतिन ने अनेक राज्य संस्थानों पर कब्जे तथा सुरक्षा अवस्थापना को अपने आदेशों से सुनिश्चित किया कि चुनाव परिणाम सरकार के लिए लाभकारी हों। लोकप्रिय एक्टिविस्ट तथा विपक्षी नेता अलेक्सेई नवलीन जैसे व्यक्ति को हिरासत में लेने जैसी राजनीतिक उत्पीड़न की कार्रवाइयां पुतिन की सत्ता पर मजबूत पकड़ का अनुभव कराती हैं जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है। पुतिन का उद्देश्य राज्य सत्ता के महत्वपूर्ण कारकों पर कब्जा बनाए रखना है ताकि रूसी राजनीति में उनकी वर्तमान सर्वोच्चता लगातार बनी रहे।

पुतिन का चुनाव अभियान हेरफेर, दुष्प्रचार तथा दबाव पर केन्द्रित था ताकि रूसी चुनाव से उनको वैधता प्राप्त हो सके। पुतिन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के साथ ही अपनी वैधता मंजूर कराना है। इससे उनका 'सार्वजनिक व्यक्तित्व' विकसित होता है और वे अंतरराष्ट्रीय संकटों में इसका लाभ उठाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जनता में उनका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है तथा सरकारी अवस्थापनाओं में जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। यह पुतिन के प्रशासन के लिए खतरा पैदा करता है। इसका अर्थ है कि रूसी राजनीति में बढ़ते उठकावों के कारण उनकी 'वैधता' पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं।

जातीय रैलियों के मामले में हाईकोर्ट ने की सुनवाई

भाजपा, कांग्रेस, सपा व बसपा को पुनः नोटिस भेजने का आदेश

विधि संवाददाता। लखनऊ

उत्तर प्रदेश में जातीय रैलियों पर रोक लगाने की मांग वाली विचाराधीन जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भाजपा, कांग्रेस, सपा व बसपा को नई नोटिस भेजने का आदेश दिया है। पीठ ने पाया कि 11 नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन में भेजी गई नोटिस इन राजनीतिक दलों को प्राप्त नहीं हो सकी है। लिहाजा नई नोटिसें भेजी जाएं।

चीफ जस्टिस अरुण भंसाली एवं जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने यह आदेश वर्ष 2013 में स्थानीय वकील मोतीलाल यादव द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग

बागपत में चेकिंग के दौरान गाड़ी से बरामद हुई डेढ़ करोड़ की नगदी पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद बागपत पुलिस-प्रशासन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार की देर रात चेकिंग के दौरान निवाड़ा चेक पोस्ट से एक गाड़ी से करीब डेढ़ करोड़ रुपए नकदी बरामद की है। गाड़ी में मौजूद दो लोगों को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस व इनकम टैक्स के अधिकारी पकड़े गए दोनों से पूछताछ कर रही है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग की नियमावली के अनुसार 50 हजार रुपए तक व्यक्ति अपने पास ले जा सकता है लेकिन बीती देर रात जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने वाली निवाड़ा चेक पोस्ट से चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से दो लोगों के साथ करीब डेढ़ करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई। पूछताछ में पकड़े गए एक व्यक्ति ने अपना नाम अनिल कुमार दिल्ली, शाहदरा का रहने वाला बताया है, जिसके दूसरा व्यक्ति अनिल कुमार का ड्राइवर है। पकड़ी गई नकदी के बाद जिला प्रशासन व पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। जिसके बाद जिला प्रशासन ने इनकम टैक्स के अधिकारियों को इस मामले की सूचना दी। पुलिस व इनकम टैक्स के अधिकारियों की पूछताछ में अनिल कुमार ने बताया कि उसने अपनी फेंकटी बेची है, बरामद नकदी उसी का भुगतान है लेकिन अधिकारी अभी भी पूछताछ में लगे हुए हैं कि कहीं ये पैसा चुनाव के दौरान दुरुपयोग में आने वाला तो नहीं है। अधिकारी कई बिन्दुओं पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पकड़ी गई डेढ़ करोड़ रुपए की नकदी को सीज कर छानबीन में जुटी है।

मेट्रीमोनियल साइट पर ठगी करके वाले इंनामी दम्पति गिरफ्तार

लखनऊ। मेट्रीमोनियल साइट पर फर्जी नाम से कई आईडी बनाकर ठगी करने वाले 25-25 हजार रुपए इंनामी दम्पति को एसटीएफ ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अश्वनी कुमार वैश्य निवासी 167/151 हीवेट रोड, विवेकानन्द नगर, थाना कोतवाली प्रयागराज और उसकी पत्नी रीतू वैश्य उर्फ रीतू यादव को एसटीएफ को पिछले काफी समय से तलाश थी। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि उक्त दम्पति कल्याणी देवी पार्क, थाना क्षेत्र अतरसुईया, प्रयागराज के पास टहलने आते हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह दोनों पति पत्नी हैं, जो मेट्रीमोनियल साइट यथा जीवन साथी,कॉम, शादी,कॉम आदि पर कई प्रकार के फर्जी नाम की आईडी बनाकर शादी के लिए युवक/युवतियों को इनवाइट करते हैं। फर्जी नाम पते पर सिम खरीदकर इस माध्यम से जुड़े लोगों से कई महीनों तक बात करते हैं और इस दौरान उनसे पैसे, जेवरात आदि की मांग करते हैं, जब उनसे पैसा एवं जेवरात आदि मिल जाता है तो मोबाइल ऑफ कर देते हैं और सिम फेंक देते हैं। इस तरह से यह लोग काफी लोगों से ठगी कर चुके हैं।



की ओर से बताया गया कि उसने ऑनलाइन जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। हालांकि रिकॉर्ड पर उक्त हलफनामा नहीं पाया गया। पीठ ने इस पर आयोग को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि तय की है। पीठ ने पूर्व के आदेश में चुनाव आयोग समेत केंद्र व राज्य सरकारों को जातीय रैलियों के विरुद्ध गाइडलाइंस बनाने का आदेश दिया

था। याचिकाकर्ता के मुताबिक पीठ ने इस बार अपने इसी आदेश के अनुपालन के संबंध में चुनाव आयोग को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। पीठ इससे पूर्व 11 नवंबर 2022 को इस मामले में प्रदेश के चार प्रमुख दलों भाजपा, कांग्रेस, सपा व बसपा को नोटिसें जारी करने का आदेश दे चुकी है। हालांकि इन दलों को नोटिस नहीं मिलने के कारण पुनः नई नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

सपा व्यापार सभा ने लिया इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का संकल्प



● चुनाव में व्यापारी भाजपा का पर्दाफाश कर उसे दे सकते हैं 440 वाट का करंट: अखिलेश यादव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी व्यापार सभा की बैठक मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के डॉ. रामनोहर लोहिया सभागार में हुई। बैठक में एकमत से बुधस्तर तक अपनी भूमिका तय करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में संकल्प लिया गया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व को मजबूती देते हुए पीडीए की विचारधारा पर आधारित इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में व्यापारी कोई कोर करण नहीं छोड़ेंगे। लोकतंत्र और संविधान को बचाने तथा देश में पुनः सकारात्मक माहौल स्थापित करने के

लिए भी सभी प्रतिबद्ध हैं। समाजवादी व्यापार सभा की बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीर बलिदानी दानदाता भामाशाह के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। बैठक की अध्यक्षता व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने की और कार्यक्रम का संचालन अभिमन्यु गुप्ता ने किया।

अखिलेश यादव ने समाजवादी व्यापार सभा के मुख्य प्रस्ताव और समाजवादी सरकार में हुए महत्वपूर्ण कार्यों की विवरण पुस्तिका का विमोचन किया तथा सदस्यता प्रमाण पत्र दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ी रही है। समाजवादी सरकार में उनके साथ न्याय होता था। आज व्यापारी वर्ग तबाह है। उसका शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। छोटे और खुदरा व्यापारी भाजपा की कुर्नीतियों से तबाह हैं। भाजपा की गलत नीतियों के चलते 30 प्रतिशत व्यापार ही बचा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में

यूपी की आधी आबादी इस बार भी चुनाव में साबित होगी बड़ा फैक्टर

● उत्तर प्रदेश में 7.17 करोड़ से अधिक है महिला मतदाताओं की संख्या, जीत-हार में निभा रही बड़ी भूमिका

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश की आधी आबादी हर बार की तरह इस बार भी चुनावों में बड़ा फैक्टर साबित होने जा रही है। सभी पार्टियां आधी आबादी को लुभाने में लगी हुई हैं लेकिन यदि पिछले कुछ चुनावों में वोटिंग पैटर्न पर नजर डालें तो आधी आबादी का रुझान पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन में रहा है। 2014 से आए इस बदलाव में 2017 के बाद और मजबूती आई है। विगत 7 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने महिला केंद्रित योजनाओं को आगे बढ़ाकर आधी आबादी को और सशक्त किया है। योगी सरकार प्रदेश में बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक के लिए योजनाएं चला रही हैं। वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई तरह की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर स्थिति के चलते महिलाएं अब बिना भय के जीवनयापन कर पा रही हैं। राज्य की महिला श्रम बल में भागीदारी दर बढ़कर 2022-23 में 32.10 प्रतिशत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप यह वृद्धि हुई है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध में सजा दिलाने में यूपी पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनकर उभरा है। महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सकें, इसके लिए नियमों का आसान बनाने का काम सरकार ने किया। खदानों में महिलाओं के काम करने पर जो कुछ बंदिश थी, वो सरकार ने हटाई है। देशभर में सैनिक स्कूलों के दरवाजे, लड़कियों के लिए खोल देने का काम भी ऐतिहासिक है। बलात्कार जैसे संगीन अपराधों की त्वरित सुनवाई के



महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के सीएम योगी के संकल्प के साथ ही किए गए प्रयासों के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। पीरियॉडिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएएस) की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की महिला श्रम बल में भागीदारी दर 2017-18 में 14.2 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 32.10 प्रतिशत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप यह वृद्धि हुई है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध में सजा दिलाने में यूपी पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनकर उभरा है। महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सकें, इसके लिए नियमों का आसान बनाने का काम सरकार ने किया। खदानों में महिलाओं के काम करने पर जो कुछ बंदिश थी, वो सरकार ने हटाई है। देशभर में सैनिक स्कूलों के दरवाजे, लड़कियों के लिए खोल देने का काम भी ऐतिहासिक है। बलात्कार जैसे संगीन अपराधों की त्वरित सुनवाई के

दीपक कुमार बने अपर मुख्य सचिव गृह

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद शासन ने मंगलवार को 1990 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को अपर मुख्य सचिव (गृह) की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके पहले प्रमुख सचिव (गृह) रहे संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, सूचना और प्रोटोकाल रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने बीते सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए छह राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, गुजरात, झारखंड और हिमांचल प्रदेश के गृह सचिवों को हटाने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने का आदेश जारी किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने प्रमुख सचिव गृह पद पर तैनात आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद को हटा दिया था। राज्य सरकार के नियुक्ति विभाग ने चुनाव आयोग के आदेश पर तीन आईएएस अफसरों का पैलन भेजा था। पैलन में वर्ष 1990 बैच के दीपक कुमार, वर्ष 1993 बैच के



आलोक कुमार द्वितीय और 1998 बैच के आईएएस अधिकारी अजय कुमार चौहान के नाम शामिल थे।

आयोग ने राज्य सरकार की ओर से मिले तीन नामों के पैलन में दीपक कुमार को गृह विभाग का दायित्व देने का आदेश दिया। जिसके बाद नियुक्ति विभाग ने दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव गृह बनाए जाने का आदेश जारी कर दिया। उनके पास अब होम, गोपन, वीजा पासपोर्ट, जेल, सतर्कता विभाग का प्रभार रहेगा। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार अभी अपर मुख्य सचिव वित्त और माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ये दोनों विभाग भी उनके पास यथावत बने रहेंगे।

इलेक्टोरल बॉण्ड मामले में खुल चुकी है भाजपा की वसूली की पोल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि देश की जनता लोकसभा चुनाव में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी भाजपा सरकार के अन्याय, अत्याचार के खिलाफ वोट करेगी। भाजपा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया। ईडी, सीबीआई और इन्कम टैक्स के छापों के बल पर वसूली की। देश के इतिहास में इस तरह की वसूली कभी नहीं हुई। भाजपा ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। संविधान विरोधी काम किया है। इलेक्टोरल बॉण्ड के मामले में देश भर में भाजपा की वसूली की पोल खुल चुकी है। चंदा के नाम पर वसूली हुई, पैकेज लिया गया। भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यह बात पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वातां के दौरान कही। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा

सरकार ने ईडी, सीबीआई और इन्कम टैक्स के जरिए विपक्षी दलों के नेताओं को प्रताड़ित किया। बदनाम किया। भाजपा में शामिल होने के लिए दबाव बनाया। पार्टियों को तोड़ने का काम किया। जनता सब देख रही है। लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा के खिलाफ खड़ी होगी। जनता ही देश में लोकतंत्र बचाएगी। भाजपा विपक्षी नेताओं पर दबाव बना कर पार्टी में तो शामिल करा सकती है लेकिन जनता को शामिल नहीं करा सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सतर्क रहना होगा। पार्टी के नेता-कार्यकर्ता चुनाव में हर स्तर पर ध्यान रखें और निगरानी करें। भाजपा देश की हर संवैधानिक संस्था को कमजोर कर रही है। यह लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में भाजपा को हराने से चुक गये तो जनता आने वाले समय में वोट नहीं डाल पायेगी। भाजपा जनता के अधिकार छीन रही है।

लोकतंत्र, संविधान और आजादी को बचाना है। व्यापारी भाजपा का पर्दाफाश कर उसे 440 वाट का करंट दे सकते हैं।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के साथ शक्तिहीन हो गए राहुल गांधी: केशव मौर्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कड़वा सच यह है, कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के साथ राहुल गांधी ‘शक्तिहीन’ हो गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लम्बोत्तुआब ढाक के तीन पात।

उप मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर लिखा कि, शक्ति स्वरूपा से शुंम्भु और निशुंम्भु लड़े थे, उनका हथ्र क्या हुआ, यह कांग्रेस के बहादुरशाह को पता होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि हमारी सरकार का प्रयास, हम गरीबी के खिलाफ युद्ध



कर रहे हैं, हम गरीबी को परास्त करके के दम लेंगे, महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार बनी, इसलिए सभी काम अच्छे से हो रहे हैं। उन्होंने अपने संदेश के जरिए

भाजपा सरकार में नहीं मिल रहा मंदिरों को उनका वार्षिक भत्ता: अजय राय

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि इलाहाबाद उच्चन्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में चिन्ता जाहिर की है कि, यह बहुत ही दुखद है कि मंदिरों को राज्य सरकार से अपना जायज हिस्सा लेने के लिए कोर्ट तक आना पड़ रहा है। ठाकुर रंगजी महाराज विराजमान मंदिर मथुरा द्वारा सरकार के खिलाफ किए गए मुकदमें में उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2020 से उनका वार्षिक भत्ता जो यूपी जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के सेक्शन 99 के तहत निर्धारित है, नहीं मिला रहा है, इतना ही नहीं उनके साथ साथ वृन्दावन के अन्य 8 मंदिरों को



वार्षिक भत्ता नहीं मिला है। मुकदमा सुन रहे न्यायमूर्ति ने सरकार की इस दलील पर अश्चर्य प्रकट किया कि मंदिरों को पैसा फंड की कमी की वजह से नहीं दिया गया।

अजय राय ने कहा कि जिस प्रदेश में मंदिरों को उनका जायज हक न मिल पा रहा हो वह राम राज्य की बात करते हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने चुनावी एजेंडे का साधने के

कांग्रेस मुख्यालय पर मनाई गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवटराम की पुण्यतिथि

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर मंगलवार को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवटराम भगवानदास कुपलानी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के उपाध्यक्ष व प्रभारी प्रशासन दिनेश कुमार सिंह ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इस मौके पर दिनेश सिंह ने कहा कि जीवटराम भगवानदास कुपलानी गांधी जी के सबसे उत्साही शिष्यों में से एक थे। उन्होंने लगभग एक दशक तक कांग्रेस के महासचिव के रूप में कार्य किया था। उनके पास शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अनुभव था और कांग्रेस के पुनर्निर्माण के लिए उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। प्रक्रियात्मक मामलों पर पार्टी और

बताया है कि अब तक 34 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में हर वर्ग का विकास हो रहा है। 12 करोड़ लोगों को इन्जत घर (शौचालय) देने का काम किया गया है और आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हुई हैं, इसलिए अबकी बार 400 पर। फिर एकबार मोदी सरकार! विकसित भारत के लिए! तीसरी बड़ी इकोनॉमी के लिए, किसान कल्याण के लिए, युवाओं को नए अवसर के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए... 400 पर।

फेक और पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखेगा चुनाव आयोग

● मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के संबंध में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उन्होंने संवाद के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए प्रचार निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तृत रूप से बताया। आदर्श आचार संहिता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का संग्रहण है, जिसके द्वारा राजनैतिक दलों, शासकीय सेवकों एवं निर्वाचन प्रक्रिया में अन्य सहभागियों को निर्वाचन के दौरान अपेक्षित आचरण करने के लिए बाध्य करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान फेक और पेड न्यूज पर आयोग की कड़ी नजर होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को फेक न्यूज के बारे में सचेत करते हुए उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में बताया कि किसी भी समाचार या गलत सूचना और मीडिया स्टोरी की पहचान व त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक एसओपी तैयार की गई है। एमसीएमसी द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की मॉनीटरिंग की जाती है।



समस्त विज्ञापन एमसीएमसी द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित किये जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने बताया कि विशिष्ट समाचार पत्रों के एक ही पृष्ठ पर, प्रतिस्पर्धी जीतेगा संबंधी प्रकाशित खबर पेड न्यूज की श्रेणी में आवेंगे। पेड न्यूज का प्रकरण सत्यापित होने पर डीआईपीआर/डीएवीपी दरों के आधार पर इसका वास्तविक या अनुमानित व्यय उम्मीदवार के चुनाव व्यय खातों में जोड़ा जायेगा। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम, पेड न्यूज आइटम के सभी विवरणों के साथ आयोग द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु भारतीय प्रेस परिषद और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को भेजा जायेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सामासि के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में निर्वाचन संबंधी कोई भी प्रचार सामग्री सिममा हॉल, टेलीविजन या किसी अन्य विधि से प्रसारित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। प्रथम चरण के मतदान से लेकर अंतिम चरण के मतदान की समाप्ति के आधे घण्टे बाद तक एक्जिट पोल भी प्रतिबंधित रहेगा। एमसीएमसी से प्रमाणन के बाद ही राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही प्रत्याशी को प्रोजेक्ट नहीं करना है बल्कि सभी को समान कवरेज देना है।

जनपद में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत धारा 144 हुई लागू

कानपुर देहात। वर्तमान में रमजान माह का आरम्भ है एवं आगामी दिनों में होलिका दहन, होलिकोत्सव, गुड फ़्राइडे एंड.उल.फ़ितरए चैत्र नवरात्रि श्रीराम नवमी आदि विशेष पर्व त्योहार मनाये जायेंगे तथा लोकसभा सामान्य निर्वाचन,2024 की अधिसूचना के अनुसार जनपद में आदर्श आचार संहिता मतगणना की तिथि तक प्रभावी है। उक्त त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्थाध्वांति व्यवस्था एवं जनमुखा बनाये रखना अतिआवश्यक है। जिसके दृष्टिगत अपर जिला मजिस्ट्रेट ,प्रशासनइए कानपुर देहात अमित कुमार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा.144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्थाध्वांति व्यवस्थाध्जन सुरूखा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं

धानीण क्षेत्र हेतु निम्नलिखित निषेधाज्ञाए पारित करता है। जनपद कानपुर देहात में किसी भी व्यक्तिध्स्स्थाध् संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम ध् माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौमनस्य को बिगड़ाने का प्रयास नहीं किया जायेगा। जनपद में कोई भी ड्रोन कैमरा का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं करेगाए किन्तु सुखा एजेंसिया इससे मुक्त रहेगी। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नहीं होगाए जिसका उद्देश्य किसी विधि विरुद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेन्स तेजाब व अन्य कोई पदार्थ की विस्प्रेटक सामग्री की श्रेणी में आता है एकत्रित नहीं करेगा साथ ही कंकड़ए पत्थर खाली बोतलोंए शीशे के टुकड़े आदि ऐसी सामग्री का

संग्रहए जिसका प्रयोग लोक व्यवस्था, शान्ति, कानून व्यवस्था, शान्ति, कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हो सकता है, अपने भवनों में या छतों या अन्य स्थानों पर कहीं नहीं करेगा और न ही रखेगा। किसी व्यक्तिध्संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम सार्वजनिक/निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे किसी जाति, पंथ, संगठन, धर्म के अनुयायिओं/ व्यक्तियों की भावनाओं को आधात पहुंचे और साम्प्रदायिक/धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के प्रचार आदि के लिए अपने साथ.साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमिए भवन आदि का किसी भी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन, दीवार अथवा अन्य स्थान पर पोस्टर, हैण्डबिल नहीं चिपकायेगा।

बिना सीएमओ की अनुमति के साठ लाख का आक्सीजन प्लांट उतारा कंपनी के वर्करीं ने

हमीरपुर। मरीजों की सुविधा के लिये दस लाख लीटर क्षमता का व साठ लाख कीमत का शासन से आया आक्सीजन प्लांट बिना सीएमओ की अनुमति के ही 36 घंटे बाद अस्पताल परिसर में कंपनी के वर्करीं ने उतार कर छुट्टी पा ली है। प्लांट लावारिस हालत में अस्पताल परिसर में पड़ा है।



सदर अस्पताल के लिये दस लाख लीटर क्षमता का साठ लाख कीमत का एलएमको आक्सीटन प्लांट शासन ने खरीद कर कारपोरेशन के समस्त कागजात दिखाये तो सीएमओ असमंजस में पड़ गये मगर जिला अस्पताल में स्थान न होने व शासन से स्पष्ट आदेश न होने के कारण सीएमओ डा.गोतम सिंह ने प्लांट उतारने से साफ ईकार कर दिया। दिल्ली से एलएमको कंपनीसे प्लांट लेकर आये कंपनी के वर्कर पंकज कुमार ने सीएमओ टंकी के पीछे प्लांट उतार दिया है। सीएमओ का कहना है कि कंपनी के वर्कर अपने रिस्क में उतार गये है। कोई बात होती है तो वह जानेगे प्लांट लेने के लिये उनको कोई शासन से आदेश नहीं है। जिले में यह सबसे भारी व अधिक क्षमता का प्लांट बताया जाता है। जिला अस्पताल के सीएमएस डा एसपी गुप्ता का कहना है कि आक्सीजन प्लांट कहा लगाया जाये सोचना पड़ेगा। यदि अस्पताल के सामने बने आवास ढहा दिये जाये तो प्लांट स्थापित किया जा सकता है।

आदर्श आचार सहिता का अनुपालन और दैनिक खर्च को व्यय लेखा में अंकन करें राजनैतिक दलः डीएम

● डीएम ने ली राजनीतिक दलों संग बैठक, बताए चुनाव के कायदे कानून

लखीमपुर खीरी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने, राजनैतिक दलों को व्यय के अनुवीक्षण से संबंधित सभी प्राविधानों से अवगत कराने के उद्देश्य से मंगलवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के संग बैठक की। इसमें आयोग की ओर से व्यय मद की दरों के बारे में दिए गए निर्देशों की जानकारी दी गई। साथ ही लेखा व्यय सही न होने पर आयोग की ओर से कार्रवाई के दिए गए निर्देशों के बारे में भी बताया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि व्यय लेखा राजनैतिक दलों के चुनाव



खर्च की पारदर्शिता को दर्शाता है। सभी राजनैतिक दल दैनिक खर्च होने वाली रकम का मदवार व्यय लेखा में अंकन करें। इससे जांच के समय किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आयोग की जवाबदेही से भी बचें। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, सी विजित, वीटर हेल्पलाइन एप्प, सुविधा ऐप सहित अन्य लिंक सहित राजनीतिक दलोंए अभ्यर्थियों द्वारा

निर्वाचन के दौरान व्यय किए जाने की सीमाए व्यय लेखों के संरक्षण के संबंध में आयोग के निर्देशों की जानकारी दी। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों व रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा.निर्देशों से भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया। सभी राजनीतिक दलों से उनके स्टार प्रचारकों की रैलियोंए रोड शो और अन्य होने वाले चुनावी आयोजनों के लिए खर्च के प्रावधान की भी जानकारी दी।

अज्ञात वाहन की टक्कर में वैन सवार तीन की मौत, एक गंभीर

फर्रुखाबाद। जहानगंज थाना क्षेत्र में आज किसी किसी ज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से एक मारुति वैन में सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया । यह जानकारीआज मोहम्मदाबाद पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार ने दी। पुलिस ने बताया कि जहानगंज थाना क्षेत्र में काली नदी पुल के समीप रात्रि कालीन पिकेट ड्यूटी पुलिस को आज मंगलवार तड़के रात्रि 1. 30 बजे सूचना मिली कि फर्रुखाबाद – काली नदी छिबरामऊ मार्ग पर थाना क्षेत्र के फैंजी पेट्रोल पंप के पास किसी अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से एक मारुति वैन के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से उसमें फंसे सवारों की चीख पुकार मची हुई है।

इसी सूचना पर जहानगंज थानाध्यक्ष भोलेद्र चतुर्वेदी अपने दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक़त के बाद घुर्घटना ग्रस्त

मारुति वैन को कटवाकर वैन में फंसे सवारों मे कन्नौज जिले के थाना छिबरामऊ के ग्राम कसावा निवासी खिलावन उर्फ दीपू व इसी जिले के थाना तालग्राम के ग्राम यूसुपुर निवासी रामजीत प्रजापति व इसी जिले के मौकमपुर पुलिया बिशनगढ़ निवासी अनमोल तथा ग्राम यूसुपुर निवासी शिवम को बाहर निकला गया। इसके बाद एम्बुलेंस 108 से इन चारों गंभीर रूप से घायलों को अचेतावस्था समीपवर्ती कन्नौज जिले के छिबरामऊ के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया जहां सरकारी चिकित्सक ने खिलावन उर्फ दीपू व रामजीत प्रजापति व अनमोल को मृत घोषित कर दिया तथा उनके साथी शिवम को उपचार के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया।जहानगंज थानाध्यक्ष भोलेद्र चतुर्वेदी ने बताया कि मारुति वैन सवार तीनों मृतकों के शवो के पोस्टमार्टम कन्नौज जिला अस्पताल में होंगे।

डीएम ने की राजनैतिक दलों के साथ बैठक

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुई। बैठक में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में आचार संहिता के अनुपालन व निर्वाचन को शांतिपूर्ण, सकृशल, सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत विभिन्न दिशा निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिये गये। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया कि वे आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रचार.प्रसार व अन्य गतिविधियों को सम्पादित करें, जिससे जनपद में सौहार्दपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर कन्ट्रोल रूम बनाया गया हैए जहां पर अपनी शिकायतें/सुझाव राजनैतिक दल नोट करा सकते है, प्राप्त शिकायतों का त्वरित रज़ान लेकर कार्यवाही की जायेगी। कोई भी राजनैतिक दल किसी मतदान बृथ के दो सौ मीटर के दायरे के अन्दर में कार्यालय नही खोलेगा।

दोषियों को कारावास व जुर्माने की सजा

लखीमपुर, खीरी। ऑपरेशन कनैक्शन के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह के दिशा निर्देशन में थाना मोहम्मदी व पसगवां की पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी व न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी द्वारा 9 आपराधिक मामलों में दोषियों को कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी द्वारा थाना मोहम्मदी क्षेत्र के ग्राम पालचक के निवासी प्रकाश पुत्र गोवर्धन कहार ए मुकदमा अपराध संख्या 374/2010 धारा 60 (2) आबकारी अधि., तेजा पुत्र राम भरोसे, मुकदमा अपराध संख्या 707/2010 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम, थाना मोहम्मदी के ग्राम बौधिया निवासी सतराम पुत्र बालक राम व राम सिंह पुत्र बाबूराम व ग्राम मुकदमा अपराध संख्या 1299/2008, धारा 60 (2) आबकारी अधि. एवं बिशनू पाल पुत्र श्रीपाल, बबलू पुत्र श्रीपाल मुकदमा अपराध संख्या 747/2006 धारा 60 (2) आबकारी

अधिनियमए ग्राम मोहम्मदपुर मजरा अमीननगर के निवासी अरसद पुत्र सिर्जु, मुकदमा अपराध संख्या 1073/2008, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, ग्राम पलचक निवासी कमलेश पुत्र राधे गिरी व बालक राम पुत्र प्यारेलाल, मुकदमा अपराध संख्या 39/2023, धारा 60,2द्वआबकारी अधिनियम, ग्राम गुलौली निवासी ललित कुमार मिश्रा पुत्र राम सागर मिश्रा मुकदमा अपराध किया 408/2002, धारा 25 आर्म्स एक्ट ए ग्राम पलिया के निवासी हंसराज पुत्र शंभू लोहार मुकदमा अपराध संख्या 353/1999, 60/62 आबकारी अधि., मा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी द्वारा थाना मोहम्मदी क्षेत्र के ग्राम पालचक के निवासी अर्धिनियम, थाना मोहम्मदी के ग्राम बौधिया निवासी सतराम पुत्र बालक राम व राम सिंह पुत्र बाबूराम व ग्राम मुकदमा अपराध संख्या 1299/2008, धारा 60 (2) आबकारी अधि. एवं बिशनू पाल पुत्र श्रीपाल, बबलू पुत्र श्रीपाल मुकदमा अपराध संख्या 747/2006 धारा 60 (2) आबकारी

जल जीवन मिशन टैंकों में हो रहा घटिया सामग्री का प्रयोग

● आधे गांव के नलों की टोटियों तक नहीं पहुंच रहा पानी ●समस्या का निस्तारण न होने पर ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी

गुरसहायगंज (कन्नौज)। केंद्र सरकार द्वारा जहां एक ओर ग्रामीण अंचलों में घर-घर पानी पहुंचाये जाने के उद्देश्य से ग्राम खाड़ेदेवर में जल जीवन मिशन द्वारा करोड़ों की लागत से पानी की टंकी बनवाई गई है। वहीं दूसरी ओर पेयजल आपूर्ति के लिए दलवाई गई मानक विहीन पाइपलाइन दर्जनों जगह से लीकेज है। जिसके कारण आधे गांव के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं जिम्मेदारों द्वारा पानी की टंकी के अतिरिक्त पानी को सोखने के लिए बनवाई जा रहे टैंकों में सेम ईट सहित मानक के अनुसार सीमेंट मौरम का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जब संवाददाता द्वारा जिम्मेदार ठेकेदार से दूरभाष पर वार्ता



जलमिशन का लागत बोर्ड, सेम ईट लगते मजदूर व पटर्नन करते ग्रामीण।

की गई तो ठेकेदार संतुष्टि जनक बयान नहीं दे सके। वही मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मो. इरफन उर्फराजू ने बताया कि आधे गांव में जगह-जगह लीकेज हुई पाइपलाइन के कारण गलियों व सड़कों में पानी भर रहा है। जबकि आधे गांव में लगी नल की टोटियों तक पानी पहुंच ही नहीं रहा है। उनके द्वारा जिम्मेदार कर्मियों को कई बार सूचना दी गई लेकिन समस्या का निस्तारण नहीं किया गया। जिस पर संवाददाता ने अपनी टीम के साथ गांव का भ्रमण किया तो पाया गया कि करीब दो दर्जन से अधिक जगहों पर

पाइपलाइन लीकेज की समस्या पाई गई। वहीं ब्लाक तालग्राम के ग्राम खाड़ेदेवर के आंशिक भाग पुरबा में पेयजल की समस्या से त्रस्त ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि पेयजल की समस्या का निस्तारण न होने की स्थिति में वह आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। अब देखना यह है कि जिम्मेदारों द्वारा केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना में बरती गई लापरवाही की जांच कर कर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे या फिर ग्रामीणों की समस्या को एक बार फिर से चलता कर देंगे।

रणजी में सिलेक्शन करवाने का झांसा देकर भाजपा नेत्री ने ठगे लाखों

फतेहपुर। भाजपा नेत्री ने एक युवा क्रिकेटर को रणजी में सिलेक्शन करवाने का झांसा देकर 4.50 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने भाजपा नेत्री और उसके दो बेटों पर धोखाधड़ी सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, कल्यानपुर थाना क्षेत्र के इटरीरा पिलखनी गढ़ निवासी अरविंद कुमार सदर कोतवाली क्षेत्र के शांतिनगर मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर क्रिकेट की कोचिंग करता है। बताया जा रहा है कि करीब एक महिने पहले उसकी मुलाकात भाजपा के महिला मोर्चा की जिला मंत्री वंदना द्विवेदी से हुई थी। इस दौरान भाजपा नेत्री ने क्रिकेटर अरविंद से कहा कि उसका बेटा अमित द्विवेदी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में रणजी टीम में सेलेक्ट हो गया है। नेत्री ने अरविंद के भी चयन कराने की बात कही। साथ ही एवज में 10 लाख रुपए की मांग की। इस पर अरविंद तैयार हो गया और नेत्री के कहने पर उसके बेटे अमित के बैंक खाते में अलग-अलग किस्तों में 4.50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। महीनों बीत जाने के बाद जब अरविंद महिला से इस बारे में जानकारी ली तो चयन हो जाने की बात कह कर महिला ने टक्का दिया। आशंका अरविंद हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पहुंचकर जानकारी की तो पता चला कि अमित द्विवेदी नाम के किसी खिलाड़ी का वहां चयन नहीं हुआ। इसके बाद वापस लौटे पीड़ित ने महिला से रुपए वापस मांगे। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान भाजपा नेत्री और उसके बेटे अमित और सुमित ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। कोतवाल राजेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में कोर्ट के आदेश पर भाजपा नेत्री और उनके दो बेटों के खिलाफधोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी के साथ अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

पैमाइश में गलत निकली नगर पंचायत की कार्यवाही

● पूर्व अध्यक्ष के निर्माण कार्य को पंचायत कर्मियों द्वारा ध्वस्त करने का मामला, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

संवाददाता। गुरसहायगंज (कन्नौज)

क्षेत्र के कस्बा समधन में पूर्व चेयरमैन के पुत्र द्वारा अपनी जमीन पर कराये जा रहे निर्माण कार्य को नगर पंचायत कर्मियों द्वारा अवैध बता कर बगैर राजस्व कर्मी के ध्वस्त किए जाने के मामले में बड़ी चूक सामने आई है। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण रूप से वैध था।

बताते चलें कि विगत महापूर्व नगर पंचायत समधन द्वारा प्रभारी निरीक्षक को संबोधित प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि समधन के पूर्व चेयरमैन



जानकारी देते बसना नेता सैयद उस्बेन का फाईल फोटो।

के पुत्र सैयद अहमद उस्बेन बड़ू द्वारा अवैध निर्माण कार्य तालाब की भूमि पर करवाया जा रहा है। जिस पर पुलिस द्वारा अवैध निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया था। लेकिन अगले दिन फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा बगैर प्रशासन के बलपूर्वक निर्माण कार्य को गिरवा दिया गया था। वहीं पूरे मामले में लेखपाल की भूमिका को भी पंचायत कर्मियों ने संदिग्ध बताया

था। पंचायत कर्मी ने लेखपाल व अन्य उच्चाधिकारिओ की साठ गांठ से नगर पंचायत की सरकारी तालाबी भूमि पर अवैध निर्माण कार्य करवाए जाने का आरोप लगाया था। जिस पर निर्माण कार्य करवा रहे बसपा नेता सैयद अहमद उस्बेन द्वारा मामले के संबंध में उच्च अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र देकर पुन जांच की मांग की गई थी। उच्चाधिकारियों को निर्देश पर एक जांच टीम का गठन किया गया जिसमें छिबरामऊ तहसील के नायब तहसीलदार सहित राजस्व निरीक्षक एवं तीन लेखपालों द्वारा जांच के उपरांत तैयारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि सैयद अहमद उस्बेन द्वारा निर्माण कार्य गाटा संख्या 20441 में करया जा रहा था जो की पूर्णता सही था। वह भूमि संक्रमणीय भूमिधर आरजी में स्थित है। तालाब की भूमि में कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया गया है इस पूर्व उक्त गाटा संख्या 2040 की राजस्व निरीक्षक की उपस्थिति में राजस्व टीम द्वारा पैमाइश की जा चुकी है।

डीएम ने की राजनैतिक दलों के साथ बैठक

● सभी राजनैतिक दल आयोग द्वारा दिये निर्देशों का करें अनुपालनः डीएम

● राजनैतिक दल आदर्श आचार सहिता का करें पालनः जिलाधिकारी

कानपुर देहात। डीएम आलोक सिंह की अध्यक्षता में राजैनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुई। लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में आचार संहिता के अनुपालन व निर्वाचन को शांतिपूर्ण, सकृशलए सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत विभिन्न दिशा निर्देश डीएम द्वारा दिये गये। डीएम ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया कि वे आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रचार.प्रसार व अन्य गतिविधियों को सम्पादित करेंए जिससे जनपद में

सौहार्दपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराया जा सके। जनपद स्तर पर कन्ट्रोल रूम बनाया गया है, अपनी शिकायतें/सुझाव राजनैतिक दल नोट करा सकते है, प्राप्त शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर कार्यवाही की जायेगी। कोई भी राजनैतिक दल किसी मतदान बृथ के दो सौ मीटर के दायरे के अन्दर में कार्यालय नही खोलेगाए राजनैतिक दल बिना अनुमति के सभा, जुलूस, रैली आदि का आयोजन नहीं कर सकेंगे। इस दौरान राजनैतिक दलों को व्यय सूची भी उपलब्ध करायी गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी दल व्यय सीमा के अन्दर ही खर्च कर सकते है। अन्य संबंधित बिन्दुओं पर भी डीएम ने विस्तृत दिशा निर्देश दिये। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पाण्डेय, भारतीय जनता पार्टी से महेंद्र कटियार, व अजय पाल, समाजवादी पार्टी से शेखू खान व डा0 नरेन्द्र सिंहए बहुजन समाज पार्टी से सर्वेश कुमारए कम्युनिस्ट पार्टी व आमआदमी पार्टी के सदस्यगण आदि मौजूद रहे।

डीएम ने एआरओ व एफएसटी टीम के अधिकारियों के साथ की बैठक दिये निर्देश

कानपुर देहात। डीएम आलोक सिंह की अध्यक्षता में एआरओ व एफएसटी टीम के अधिकारियों के साथ बैठक मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकृशल, शांतिपूर्ण सम्पन्न करायें जाने के दृष्टिगत विभिन्न दिशा निर्देश संबंधित को दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि गठित एफएसटी टीम अपने.अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहकर मौलद कोड ऑफ कन्डक्ट/आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। एफएसटी टीम द्वारा कोई भी कार्यवाही अण्डर वीडियोग्राफी की जायेगी, एफएसटी टीम कन्ट्रोल रूम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगी, कोई भी एफएसटी टीम अपने क्षेत्र से बाहर विचरण/भ्रमणशील नहीं रहेगी। आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले, उसी के अनुरूप कार्यवाही करें।

रफह में इजराइल के सैन्य अभियान की आशंका से बहुत चिंतित हूं : बाइडन ने नेतन्याहू से कहा

भाषा । वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वह इजराइल द्वारा गाजा सिटी और खान यूनिस की तरह ही रफह में बड़ा सैन्य अभियान चलाए जाने की आशंका से काफी चिंतित हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने यह जानकारी दी।

सुलिवन ने सोमवार को अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नेतन्याहू सोमवार को बाइडन के साथ फोन पर हुई बातचीत में दक्षिणी गाजा के रफह शहर में हमास आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए किसी वैकल्पिक तरीके और जमीनी स्तर पर बड़ा हमला किए बगैर मिस्‍र-गाजा सीमा

को सुरक्षित बनाने पर चर्चा करने के लिए इजराइली अधिकारियों का एक दल वाशिंगटन भेजने पर राजी हो गए।

यह एक महीने में पहली बार है जब दोनों नेताओं ने फोन पर बात की है। सुलिवन ने बताया कि बाइडन और नेतन्याहू ने रफह को लेकर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ने बताया कि वह इजराइल द्वारा गाजा सिटी और खान यूनिस की तरह ही रफह में बड़ा सैन्य अभियान चलाने की आशंका को लेकर वह क्यों इतने चिंतित हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बताया कि 10 लाख से अधिक लोगों ने रफह में शरण ली है। उन्होंने कहा कि वे गाजा सिटी से खान यूनिस और फिर रफह गए, अब उनके पास कोई सुरक्षित जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि गाजा के अन्य प्रमुख शहरों को

बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इजराइल ने अमेरिका या दुनिया को यह योजना नहीं बताई है कि वह कैसे या कहाँ उन नागरिकों को सुरक्षित स्थानांतरित करेगा।

सुलिवन ने कहा कि रफह मिस्‍र से गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने का प्रमुख प्रवेश बिन्दु है और शहर में सैन्य अभियान से यह बंद हो जाएगा।

उन्होंने कहा, रफह मिस्‍र के साथ लगती सीमा पर स्थित है और मिस्‍र ने वहां एक बड़े सैन्य अभियान को लेकर गहरी चिंता जताई है तथा इसके परिणामस्वरूप इजराइल के साथ भविष्य में अपने संबंधों को लेकर सवाल भी उठए हैं।

उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि हमास को रफह या कहीं और पनाह न दी जाए। लेकिन वहां एक बड़ा

जमीनी अभियान चलाना गलती होगी। इससे कई निर्दोष जान जाएंगी, पहले से ही गंभीर मानवीय संकट और बढ़ेगा, गाजा में अराजकता बढ़ेगी तथा इजराइल अंतरराष्ट्रीय रूप से और अलग-थलग होगा।

सुलिवन ने बताया कि दोनों नेताओं ने गाजा में हमास तथा अन्य आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के बदले में कई हफ्तों के लिए तत्काल संघर्ष विराम को लेकर चल रही बातचीत पर भी चर्चा की।

बाइडन ने इजराइल की दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि इजराइल को हमास पर हमले करने का अधिकार है जिसने नरसंहार के बाद से यहूदी लोगों पर सबसे वीभत्स हमला किया है।

सर्जरी के बाद पहली बार केट और प्रिंस विलियम सार्वजनिक रूप से दिखे

एपी । लंदन

प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी कैथरीन का उनके विंडसर स्थित घर के पास एक दुकान का वीडियो सामने आया है जो दो महीने पहले केट की पेट की सर्जरी के बाद उनका यह पहला फुटेज है।



द सन अखबार की खबर में यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि लंदन के पश्चिम में विंडसर में यह वीडियो शनिवार को बनाया गया।

अखबार ने सोमवार को एक छोटा क्लिप जारी किया जिसमें विलियम और केट को मुस्कुराते हुए, हाथ में खरीदे गए सामान के थैले लेकर चलते हुए देखा जा सकता है।

द सन ने वीडियो बनाने का दावा करने वाले नेल्सन सिल्व्वा नामक व्यक्ति के हवाले से कहा, केट खुश दिख रही थीं। हालांकि, दोनों के केनसिंगटन पैलेस स्थित कार्यालय ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है।

पैलेस ने कहा कि केट (42) ईस्टर के बाद आधिकारिक कामकाज संभालेंगी।

इससे पहले उनकी सार्वजनिक गैर-मौजूदगी को लेकर तरह-तरह की अफवाहें चल रही थीं। पैलेस ने इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की थी, लेकिन कहा था कि केट की समस्या कैसर से संबंधित नहीं है।

सिलिव्कॉन वैली के भारतीय-अमेरिकी पेशेवरों ने प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए हवन किया

भाषा । वाशिंगटन

सिलिकॉन वैली के भारतीय-अमेरिकी तकनीकी पेशेवरों ने भारत में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जीत के लिए एक मंदिर में विशेष हवन कराया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी (ओएफबीजेपी) और यूएसए सैन फ्रांसिस्को वे एरिया चैप्टर द्वारा आयोजित हवन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह केवल एक अनुष्ठान नहीं था बल्कि अधिकांश भारतीयों और प्रवासी भारतीयों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक सामूहिक आह्वान था। ओएफबीजेपी ने कहा कि भारतीय समुदाय आगामी संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी

(भाजपा) की निर्णायक जीत की प्रार्थना करने के लिए एक साथ आया और अबकी बार, 400 पार का नारा दोहराया। उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जुन तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित

सरकार को असहमति पर अंकुश लगाने की अधिक शक्ति दी

एपी । हांगकांग

हांगकांग की विधायिका ने मंगलवार को एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया जो सरकार को असहमति खत्म करने की अधिक शक्ति प्रदान करता है। इसे 2019 में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के कारण हुई व्यापक राजनीतिक कार्वाई के नवीनतम कदम के रूप में देखा जा रहा है।

विधायिका ने मंगलवार को एक विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षा कानून पारित किया। यह चार साल पहले चीन द्वारा लागू एक ऐसे ही कानून से भी कठोर है, जिसने वित्तीय केंद्र में विपक्षी आवाजों को

काफी हद तक खामोश कर दिया है।

हांगकांग की विधान परिषद में चुनावी बदलाव के बाद चीन के प्रति निष्ठा रखने वालों का दबदबा है। विधायी परिषद ने विरोधी आवाज को दबाने वाले कानून को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आठ मार्च को विधेयक पेश किया गया था। हांगकांग के नेता जॉन ली द्वारा कानून को पूरी गति से से आगे ले जाने की अपील के बाद एक समिति ने एक सप्ताह तक दैनिक बैठकें कीं।

कानून में कई प्रकार की उन कार्वाइयों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है जिन्हें अधिकारी राष्ट्रीय

सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। इनमें सबसे गंभीर देशद्रोह और विद्रोह है। इनमें आजीवन कारावास तक की सजा भी शामिल है। देशद्रोही किताब या सामग्री रखने सहित छोटे अपराधों के लिए भी कई वर्षों की जेल हो सकती है। कुछ प्रावधान दुनिया में कहीं भी किए गए कृत्यों के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति देते हैं।

आलोचकों ने चिंता जताई है कि नया कानून नागरिक स्वतंत्रता को और कमजोर कर देगा जिसे चीन ने तब 50 वर्षों तक संरक्षित करने का वादा किया था जब 1997 में पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश चीनी शासन में वापस आया था।

यूक्रेन में अपने आक्रमण से पीछे नहीं हटेगा रूस, बफर जोन बनाएगा: पुतिन

एपी । मांस्को

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद कहा कि मांस्को यूक्रेन में अपने आक्रमण से पीछे नहीं हटेंगा और उसकी यूक्रेन के लंबी दूरी के और सीमा पर हमलों से रक्षा करने के लिए एक बफर जोन बनाने की योजना है। रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में प्रागति की है लेकिन यह प्रागति थोड़ी रही है और महंगी साबित हुई है। यूक्रेन ने रूस में तेल रिफाइनरी और डिपो को निशाना बनाने के लिए अपने लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन में स्थित क्रेमलिन के प्रतिद्वंद्वियों के एक समूह ने सीमा पार हमले भी शुरू किए हैं। पुतिन ने रविवार देर रात कहा, हम

जरूरी होने पर यूक्रेनी सरकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों पर कुछ सुरक्षित क्षेत्र बनाने पर विचार करेंगे।

पुतिन ने कहा कि इस सुरक्षित क्षेत्र (बफर जोन) में दुश्मन के पास उपलब्ध विदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर चुसना मुश्किल होगा।

रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा था कि देश में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने जीत दर्ज की है और उन्होंने रिकॉर्ड मत प्रतिशत के साथ राष्ट्रपति पद का पांचवां कार्यकाल हासिल किया है।

पुतिन ने पश्चिमी देशों को यूक्रेन में सैन्य बलों को तैनात करने के

खिलाफ एक बार फिर चेतावनी दी। उन्होंने आगाह किया कि रूस और नाटो के बीच एक संभावित संघर्ष से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से महज एक कदम पीछे रह जाएगी।

गौरतलब है कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने हाल में कहा था कि यूक्रेन में पश्चिमी सेना भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

कीव के साथ शांति वार्ता की संभावनाओं पर पुतिन ने दोहराया कि रूस बातचीत के लिए तैयार है लेकिन वह ऐसे युद्धविराम के झंझसे में नहीं आएगा जिससे यूक्रेन को फिर से हथियारबंद होने में मदद मिले।

श्रीलंक : विक्रमसिंघे ने मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दिए

भाषा । वाशिंगटन

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अपने मंत्रिमंडल को इस साल के उत्तरार्द्ध में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश ऐसे समय दिया गया है, जब नकदी संकट से जुड़ा रहा देश अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से उबरने का प्रयास कर रहा है। अगले राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग को संतिर्बर तक करनी है और नवंबर के मध्य तक तदतदन संपन्न कराना है। संसद का कार्यकाल अगस्त 2025 में पूरा होगा, लेकिन राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के पास अगस्त 2020 में निर्वाचित 225 सदस्यीय असेंबली को भंग करके चुनाव किसी भी समय आयोजित करने की शक्ति है। समाचार पोर्टल डेली मिरर ने सूत्रों के हवाले से मंगलवार को बताया कि अटक्नों को समाप्त करते हुए , विक्रमसिंघे ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान घोषणा की कि पहले राष्ट्रपति चुनाव होगा और चुनाव के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया। विक्रमसिंघे (74)ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि पहले राष्ट्रपति चुनाव होना चाहिए और उसके अनुरार व्यवस्था की जाएगी। श्रीलंक के 2022 में गंभीर आर्थिक संकट में फंसने के बाद यह पहला चुनाव होगा। आर्थिक रूप से संकटग्रस्त देश, खाद्य पदार्थ और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी से जुड़ा रहा है, और इसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है। दिवालिया घोषित होने के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसकी वजह से तत्कालीन राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा और अंततः अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।



कििम जोंग उन ने सियोल को निशाना बनाने वाली प्रणाली के अभ्यास का निरीक्षण किया

एपी । सियोल

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने परमाणु आयुद्ध हो जाने में सक्षम उन रॉकेट को दागे जाने के अभ्यास का निरीक्षण किया जिन्हें कथित तौर पर दक्षिण कोरिया की राजधानी को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

सरकारी मीडिया की खबर के मुताबिक, किम ने प्रतिद्वंद्वियों से बढ़ते टकराव के मद्देनजर अपने युद्ध निवारक उपाय बढ़ाने का संकल्प लिया है।

इससे एक दिन पहले दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं ने कहा था कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तटीय क्षेत्र की ओर कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी है।

उत्तर कोरिया ने सोमवार को जिन तीन प्रणालियों का परीक्षण किया है कि उनमें 600 मिमी बहु रॉकेट प्रक्षेपक भी शामिल है जो सामरिक परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम है।

उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी (केसीएनए) द्वारा प्रकाशित फोटो में दिख रहा है कि प्रक्षेपण वाहन से एक साथ कम से कम छह रॉकेट दागे गए।



इससे एक दिन पहले दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं ने कहा था कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तटीय क्षेत्र की ओर कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी है।

उत्तर कोरिया ने सोमवार को जिन तीन प्रणालियों का परीक्षण किया है कि उनमें 600 मिमी बहु रॉकेट प्रक्षेपक भी शामिल है जो सामरिक परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम है।

उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी (केसीएनए) द्वारा प्रकाशित फोटो में दिख रहा है कि प्रक्षेपण वाहन से एक साथ कम से कम छह रॉकेट दागे गए।

इससे एक दिन पहले दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं ने कहा था कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तटीय क्षेत्र की ओर कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी है।

उत्तर कोरिया ने सोमवार को जिन तीन प्रणालियों का परीक्षण किया है कि उनमें 600 मिमी बहु रॉकेट प्रक्षेपक भी शामिल है जो सामरिक परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम है।

उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी (केसीएनए) द्वारा प्रकाशित फोटो में दिख रहा है कि प्रक्षेपण वाहन से एक साथ कम से कम छह रॉकेट दागे गए।

इससे एक दिन पहले दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं ने कहा था कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तटीय क्षेत्र की ओर कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी है।

उत्तर कोरिया ने सोमवार को जिन तीन प्रणालियों का परीक्षण किया है कि उनमें 600 मिमी बहु रॉकेट प्रक्षेपक भी शामिल है जो सामरिक परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम है।

उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी (केसीएनए) द्वारा प्रकाशित फोटो में दिख रहा है कि प्रक्षेपण वाहन से एक साथ कम से कम छह रॉकेट दागे गए।

अमेरिकी सीनेटर ने सीएए पर चिंता व्यक्त की

भाषा । वाशिंगटन

अमेरिका के एक सीनेटर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने के वास्ते भारत सरकार द्वारा नियमों को अधिसूचित किए जाने पर चिंता जताते हुए कहा है कि जैसे-जैसे अमेरिका-भारत संबंध गहराते जा रहे हैं, यह अहम है कि सरायोज धर्म से परे सभी के मानवाधिकारों की रक्षा के साझा मूल्यों पर आधारित हो।

भारत सरकार ने पिछले हफ्ते नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 का लागू कर दिया था जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऐसे गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है जिनके पास दस्तावेज़ नहीं हैं और वे

31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे।

भारत सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि इससे भारतीय मुस्लिमों को चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीएए उनकी नागरिकता प्रभावित नहीं करता है और समुदाय का इससे कुछ लेना-देना नहीं जिनके पास हिंदुओं के समान ही अधिकार हैं।

सीनेट की शक्तिशाली विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर बेन कार्डिन ने कहा, मैं विवादस्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के भारत सरकार के फैसले से, खासकर भारत के मुस्लिम समुदाय पर इस कानून के संभावित प्रभाव से बहुत चिंतित हूं। मामले को बदतर बनाने वाली बात यह है कि इसे रमजान के पवित्र महीने के दौरान लागू

किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, जैसे-जैसे अमेरिका-भारत संबंध गहराते जा रहे हैं, यह अवसर महत्वपूर्ण है कि हमारा सहयोग धर्म से परे सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा के हमारे साझा मूल्यों पर आधारित हो।

पिछले हफ्ते अमेरिका के विदेश विभाग ने भी सीएए को अधिसूचित करने को लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों हैं।

भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा सीएए की आलोचना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि यह ैगलत सूचना पर आधारित और अनुचित है।

एक अलग बयान में,

हिंदू पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी कलेक्टिव (हिंदूपैक) और ग्लोबल हिंदू हैरिटेज फाउंडेशन ने सीएए का समर्थन किया है।

इन संगठनों ने कहा कि इस कानून में भारत के पड़ोसी देशों के प्रताड़ित हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी अल्पसंख्यकों को त्वरित नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि यह वैश्विक मानवीय सिद्धांतों के अनुरूप धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ व्यक्तियों और परिवारों की सुरक्षा के प्रति भारत के समर्पण को रेखांकित करता है।

हिंदूपैक के संस्थापक और सह-संयोजक अजय शाह ने कहा, सीएए भारत के किसी भी नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। इस कानून को गैर-धर्मनिरपेक्ष बताया जाना निराधार

है। भारत के पड़ोसी देशों में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता है।

उन्होंने कहा, अमेरिकियों के तौर पर, हम इस बात से निराश हैं कि अमेरिकी मूल्यों और प्रताड़ित लोगों के मानवाधिकारों के लिए खड़े होने के बजाय, हमारी सरकार ने इस मानवीय प्रयास का विरोध करने का फैसला किया है।

ग्लोबल हिंदू हैरिटेज फाउंडेशन के वीएस नाथपॉल ने कहा, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 अल्पसंख्यकों की दुर्दशा से संबंधित है, जो हमारे पड़ोसी इस्लामी देशों में क्रूरता, उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण, हत्या, बलात्कार और सभी प्रकार के अत्याचारों का सामना कर रहे हैं, जहां धर्मनिरपेक्षता, शांति और मानवता का विचार टिक नहीं सकता है।

आसिफ भुट्टो ने पिता द्वारा खाली की गई सीट पर उपचुनाव के लिए भरा नामांकन

भाषा । इस्लामाबाद

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और दिवंगत प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की सबसे छोटी बेटी आसिफ भुट्टो ने सिंध प्रांत में नेशनल असेंबली की एक सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दायित्व कर देश की उथल-पुथल वाली राजनीति में कद

